mediaauditornews@gmail.com mediaauditor Epaperdainikmediaauditor.in mediaauditor वर्ष-29 अंक-66 पृष्ठ-8 मूल्य-3 रूपये

रीवा

08 मार्च 2025 शनिवार

दैनिक मीडिया ऑडीटर

दैनिक मीडियाऑडीटर

रीवा, सतना से एक साथ प्रकाशित

शेड्यूल पर भड़के... @ पेज 7

महाकुंभ के बाद होली में विश्व रिकॉर्ड बनाने को तैयार है योगी सरकार

वृंदावन (एजेंसी)। महाकुंभ में कई विश्व रिकॉर्ड बनाने के बाद उत्तर प्रदेश की योगी सरकार होली में भी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की तैयारी कर रही है। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से शुक्रवार को कहा गया

● वृंदावन में 2000 से ज्यादा विधवाएं खेलेंगी रंग

कि वृंदावन में 2,000 से अधिक विधवाओं के साथ होली का आयोजन करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह बनाने का प्रयास किया जाएगा। राज्य का पर्यटन विभाग और कल्याणकारी संगठन पवित्र शहर में संयुक्त रूप से इस कार्यक्रम की मेजबानी करेंगे।

एक बयान के अनुसार, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के अधिकारी प्रमाणन प्रक्रिया की देखरेख और सुविधा के लिए मौजूद रहेंगे। सरकार की तरफ से कहा गया ÷2025 में, योगी सरकार, सामाजिक कल्याण संगठनों के साथ मिलकर, 2,000 से अधिक विधवाओं के साथ सबसे बड़े होली समारोह का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का प्रयास करेगी।

इस कार्यक्रम में जैविक रंगों का उपयोग किया जाएगा जिसमें लोकगीत, पारंपरिक नृत्य और भक्ति संगीत शामिल होंगे। यह ध्यान देने योग्य है कि यह शायद अपनी तरह का पहला प्रयास है। विधवाओं की होली एक अनूठा सांस्कृतिक उत्सव है। परंपरागत रूप से, भारत में विधवाओं से होली जैसे उत्सवों सहित सांसारिक सुखों का त्याग करने की अपेक्षा की जाती थी। हालांकि, वृंदावन में शरण लेने वाली हिंदू विधवाएं वार्षिक उत्सव में भाग लेकर इस सदियों पुरानी परंपरा को चुनौती देने की कोशिश करती हैं। होली आमतौर पर दो दिनों तक मनाई जाती है। इस साल, छोटी होली या होलिका दहन 13 मार्च को होगा। रंगवाली होली, जिसे धुलंडी के नाम से भी जाना जाता है, 14 मार्च को है।

महाकुंभ में बने ये रिकॉर्ड: 66.30 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आए, अमेरिका की आबादी से दोगुने लोग पहुंचे,193 देशों की आबादी से ज्यादा महाकुंभ में आए,सिर्फ भारत-चीन की आबादी महाकुंभ आए श्रद्धालुओं से ज्यादा,120 करोड़ हिंदुओं में से 66 करोड़ से ज्यादा की डुबकी, दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम से 166 गुना बड़ा मेला एरिया, 4 हजार हेक्टेयर में महाकुंभ मेला जोन का स्ट्रक्चर, 4 लाख से ज्यादा टेंट-तंबू, 1.5 लाख टॉयलेट बने, गंगा सफाई का रिकॉर्ड बना, 4 अलग अलग स्थानों पर 360 लोगों द्वारा सफाई करने का रिकॉर्ड, हैंड पेंटिंग में - 10,102 लोगों का रिकॉर्ड, पहले 7660 लोगों का था, झाड़ू लगाने में- 19000 लोगों का रिकॉर्ड बना, पहले 10,000 लोगों का था

संक्षिप्त समाचार

आयरलैंड में आतंकवाद पर बरसे जयशंकर

लंदन (एजेंसी)। विदेश मंत्री एस.जयशंकर ने आयरलैंड में यूनिवर्सिटी कॉलेज डबलिन में अपने संबोधन के दौरान आतंकवाद पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि इससे प्रतिबद्धता के साथ निपटा जाएगा। जयशंकर ने विदेश नीति के विभिन्न मुद्दों पर अपने विचार रखे और आतंकवाद के खिलाफ भारत-आयरलैंड के साझा दृष्टिकोण को रेखांकित करने के लिए जून 1985 में एयर इंडिया विमान पर हुए आतंकवादी हमले का संदर्भ दिया। विदेश

मंत्री ने कहा कि पश्चिमी कॉर्क में आयरिश गांव अहाकि स्ता, कनिष्क बम विस्फोट आपदा का गवाह है, जिसमें 329 लोगों की मौत हो गई थी। ये घटना आयरलैंड के तट पर हुई थी। जयशंकर ने कहा, ''संघर्षों के बारे में एक विशेष बात, क्योंकि यह आज भारत के लिए एक बहुत ही प्रमुख मुद्दा है; हमारा हमेशा से यह मानना ??रहा है कि इस युग में मतभेदों को युद्ध के मैदान में नहीं सुलझाया जा सकता और न ही सुलझाया जाना चाहिए।'' वह बृहस्पतिवार को 'भारत का विश्व के प्रति दृष्टिकोण' विषय पर अग्रणी आयरिश शोध संस्थान में छात्रों, शिक्षाविदों और प्रवासी समुदाय के सदस्यों को संबोधित कर रहे थे। जयशंकर ने कहा, ''संघर्ष के बारे में बात करते हुए, आतंकवाद का मुकाबला करने पर भी कुछ कहना उचित होगा, खासकर ऐसे देश के विदेश मंत्री के रूप में जो लंबे समय से आतंकवादी प्रयासों का शिकार रहा है।'' उन्होंने कहा, ''आयरलैंड के अहाकिस्ता गांव में एक स्मारक पट्टिका है जो आयरलैंड के तट पर हुए एयर इंडिया के कनिष्क विमान बम विस्फोट के 329 पीड़ितों की याद में स्थापित की गई है। यह हमेशा याद दिलाता है कि यह एक सतत चुनौती है जिससे समग्र रूप से बहुत अधिक संकल्प और प्रतिबद्धता के साथ निपटने की आवश्यकता है।''

यमन और जिबूती के तट पर डूबी प्रवासियों की नौका

काहिरा (एजेंसी)। यमन और जिबूती के तटवर्ती जलक्षेत्र में चार नौकाओं के पलट जाने से बड़ा हादसा हुआ है। एक साथ 4 नौकाएं डूबने से कम से कम 2 व्यक्तियों की मौत हो गई है और 186 लापता हैं। राहत और बचाव दल को जब इस हादसे की जानकारी मिली तो वह मौके पर पहुंच गए। तटवर्ती क्षेत्र में घटनास्थल पर लापता लोगों के लिए तलाशी अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन अभी तक उनका कोई पता नहीं चल सका है। इससे मौतों की संख्या बढ़ने की आशंका है।

बता दें कि इन नौकाओं पर अफ्रीकी प्रवासी सवार थे। यह जानकारी संयुक्त राष्ट्र प्रवासन एजेंसी ने दी है। अंतरराष्ट्रीय प्रवासन संगठन (आईओएम) प्रवक्ता तमिम एलियन ने बताया कि इनमें से दो नौकाएं बृहस्पतिवार देर रात को यमन के तट के पास पलट गईं। उन्होंने बताया कि चालक दल के दो सदस्यों को बचा लिया गया, लेकिन 181 प्रवासी और यमन के पांच चालक दल के सदस्य अभी भी लापता हैं। उन्होंने बताया कि लगभग उसी समय छोटे से अफ्रीकी देश जिबूती के पास दो अन्य नौकाएं भी पलट गईं।उन्होंने बताया कि प्रवासियों के दो शव बरामद किए गए और नौका पर सवार सभी लोगों को बचा लिया गया। लगभग एक दशक के गृहयुद्ध के बावजूद, यमन पूर्वी अफ्रीका और सोमाली प्रायद्वीप से खाड़ी देशों में काम के लिए जाने वाले प्रवासियों के लिए एक प्रमुख मार्ग है। हर साल हजारों लोग इस मार्ग से यात्रा का प्रयास करते हैं। तस्कर अक्सर प्रवासियों को खतरनाक, भीड़-भाड़ वाली नौकाओं पर यमन पहुंचाने के लिए लाल सागर या अदन की खाड़ी को पार करते हैं।

तमिलनाडु के सीएम स्टालिन ने दक्षिण भारत के मुख्यमंत्रियों समेत अन्य राज्यों को लिखा पत्र, मांगा समर्थन

चेन्नई (एजेंसी)। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने दक्षिण भारत के राज्यों समेत विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा है। स्टालिन ने केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) और परिसीमन (डिलिमिटेशन) के मुद्दे पर समर्थन मांगा है। स्टालिन ने कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) और परिसीमन (डिलिमिटेशन) पर समर्थन देने की मांग की। स्टालिन मुख्यमंत्रियों को 22 मार्च को चेन्नई में होने वाली परिसीमन समिति की बैठक में शामिल होने की अपील की है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने पत्र में कहा कि मैं दो विशिष्ट अनुरोधों के साथ आपको लिख रहा हूँ। स्टालिन ने केंद्र सरकार की प्रस्तावित परिसीमन प्रक्रिया पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने चेतावनी दी कि यह प्रक्रिया तमिलनाडु जैसे राज्यों के प्रभाव को कम कर सकती है, जिन्होंने देश के भविष्य को आकार देने में अपनी जनसंख्या को सफलतापूर्वक नियंत्रित किया है। पत्र में स्टालिन ने बताया कि पिछली परिसीमन प्रक्रिया 1952, 1963 और 1973 में आयोजित की गई थी, लेकिन 1976 में 42वें संशोधन द्वारा 2000 के बाद पहली जनगणना तक रोक दी गई थी। 2002 में इस रोक को 2026 के बाद की जनगणना तक बढ़ा दिया गया था। हालांकि, 2021 की जनगणना में देरी के कारण, परिसीमन प्रक्रिया अपेक्षा से पहले हो सकती है, जिसका संभावित रूप से उन राज्यों पर असर पड़ सकता है जिन्होंने अपनी जनसंख्या को नियंत्रित किया है और बेहतर शासन हासिल किया है।

दिल्लीवालों को आज मिलेंगी दो सौगातें

महिलाओं से किया वादा होगा पूरा साथ मिलेगा होली-दिवाली का गिफ्ट

नई दिल्ली (एजेंसी)। दिल्ली में सरकार बनाने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनावी वादों को पूरा करना शुरू कर दिया है। रेखा गुप्ता ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते ही यमुना नदी की सफाई का अभियान शुरू कर दिया है। अब शनिवार को वह दिल्लीवासियों को दो बड़े तोहफे देने जा रही हैं। होली से पहले दिल्ली की कैबिनेट शनिवार (8 मार्च) को दो बड़ी योजनाएं पास करने वाली है। रेखा गुप्ता की अगुआई वाली सरकार महिला समृद्धि योजना और होली-दिवाली में सिलेंडर देने की योजना शनिवार को पास करेगी।

महिला समृद्धि योजना की घोषणा शनिवार 12 बजे के बाद होगी। इसके साथ ही होली-दीवाली में एक सिलेंडर देने की भी घोषणा कल होगी। शनिवार सुबह 11 बजे दिल्ली कैबिनेट में इन दोनों योजनाओं को पास कर दिया जाएगा। इसके बाद जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में दोनों योजनाओं को लागू करने की घोषणा की जाएगी।

भारतीय जनता पार्टी ने 17 जनवरी के दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के लिए अपना संकल्प पत्र जारी किया था। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली की गरीब महिलाओं के लिए हर महीने 2500 रुपये देने का वादा किया था। सिलेंडर पर 500 रुपये की सब्सिडी और होली, दीवाली पर एक-एक सिलेंडर मुफ्त देने का वादा किया गया था। इसके साथ ही जेपी नड्डा ने बताया था कि दिल्ली में जो जन कल्याण की योजनाएं चल रही हैं, वो सारी योजनाएं भाजपा की सरकार बनने पर भी जारी रहेंगी। उन सभी योजनाओं का ज्यादा कारगर तरीके से सुदृढ़ीकरण किया जाएगा और उन्हें भ्रष्टाचार से मुक्त भी किया जाएगा।

70 विधानसभा सीटों वाली दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने 48 सीटें जीती और सरकार बनाई। वहीं, आम आदमी पार्टी महज 22 सीटों पर सिमट गई। बीजेपी ने लंबी चर्चा के बाद रेखा गुप्ता को दिल्ली की मुख्यमंत्री चुना।

400 से ज्यादा उर्दू स्कूलों में अनियमितता

मुंबई (एजेंसी)। महाराष्ट्र में उर्दू मीडियम के अल्पसंख्यक स्कूलों में बड़े पैमाने पर अनियमितता सामने आई है। 400 से ज्यादा स्कूलों की शिकायत मिलने के बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जांच के आदेश दिए हैं। अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष ने कई स्कूलों पर एफआईआर दर्ज कराई है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। महाराष्ट्र में लगभग 3500 उर्दू मीडियम के अल्पसंख्यक दर्जा प्राप्त स्कूल हैं। इनमें से 400 से ज्यादा स्कूलों में कर्मचारियों पर दबाव बनाकर धन उगाही, महिला शिक्षकों का शोषण, शिक्षक पद पर संस्थान में अपने परिवार के सदस्यों की नियुक्ति, एक ही स्कूल परिसर में दो-दो स्कूल चलाने की शिकायतें अल्पसंख्यक आयोग को मिली हैं। अल्पसंख्यक आयोग का मानना है कि उर्दू स्कूलों में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ चल रहा है। स्कूल चलाने के लिए सरकार फंड देती है, लेकिन बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ हो रहा है। अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष प्यार खान ने कहा कि बड़े पैमाने पर इन स्कूलों में भ्रष्टाचार किया जा रहा है और कई स्कूलों पर एफआईआर दर्ज भी की गई है। एक शिक्षक ऐसा भी मिला, जो क्लीनिक चलाता है और कभी स्कूल नहीं गया।

रणवीर इलाहाबादिया, अपूर्वा मखीजा ने एनसीडब्ल्यू से मांगी माफी

इंडियाज गॉट लैटेंट विवाद, कहा- यह पहली और आखिरी बार

दिल्ली (एजेंसी)। यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया और अपूर्वा मखीजा ने 'इंडियाज गॉट लैटेंट' पर की गई अपनी आपत्तिजनक टिप्पणियों को लेकर राष्ट्रीय महिला आयोग से लिखित में माफी मांगी है। आयोग की अध्यक्ष विजया रहाटकर ने शुक्रवार को यह जानकारी दी और कहा कि ऑनलाइन कार्यक्रम में की गई उनकी टिप्पणियां 'कतई स्वीकार्य नहीं' हैं। इलाहाबादिया, मखीजा और शो के निर्माता सौरभ बोथरा एवं तुषार पुजारी गुरुवार को यहां राष्ट्रीय महिला आयोग के समक्ष पेश हुए। सूत्रों के अनुसार, दोनों यूट्यूबर्स से कई घंटे तक पूछताछ की गई। रहाटकर ने शुक्रवार को संवाददाता सम्मेलन में कहा कि राष्ट्रीय महिला आयोग अनुचित भाषा के प्रयोग को बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा, 'तुषार पुजारी, सौरभ बोथरा, अपूर्वा मखीजा और रणवीर इलाहाबादिया-चार लोग आयोग के समक्ष पेश हुए। आयोग अनुचित भाषा के इस्तेमाल को स्वीकार नहीं करेगा। ऐसी टिप्पणियां कतई स्वीकार्य नहीं हैं।'

रहाटकर ने कहा कि इन लोगों ने अपनी टिप्पणी पर खेद व्यक्त किया है। उन्होंने कहा, 'सामाजिक प्रभाव को ध्यान में रखते हुए उन्हें नोटिस जारी किए गए थे।

वे आयोग के समक्ष पेश हुए और गहरा खेद व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि उन्हें इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी और माफीनामा दिया है।'

रहाटकर ने संवाददाताओं से कहा कि उन्होंने कहा कि उनसे बहुत बड़ी गलती हुई है और वे भविष्य में ऐसी गलती नहीं दोहराएंगे। रहाटकर ने कहा कि उन्होंने कहा कि वे यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले शब्दों से किसी को ठेस न पहुंचे। रहाटकर ने कहा कि इलाहाबादिया ने विशेष रूप से एनसीडब्ल्यू को आश्वासन दिया कि वह भविष्य में अधिक सावधान रहेंगे।

उन्होंने कहा, 'यह पहली और आखिरी बार है जब ऐसी गलती हुई है। अब मैं सोच समझ कर सम्मान के साथ महिलाओं के बारे में कुछ बोलूंगा।'

हाई कोर्ट ने रद्द किया ईडी का समन

एमयूडीए केस में सीएम सिद्धरामैया की पत्नी को बड़ी राहत

बेंगलूरु (एजेंसी)। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को बड़ी राहत देते हुए कर्नाटक हाई कोर्ट ने मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (मुडा) भूमि आवंटन मामले में उनकी पत्नी बीएम पार्वती और शहरी विकास मंत्री बिरथी सुरेश को जारी ईडी के समन को रद्द कर दिया। ईडी ने पार्वती को 28 जनवरी को सुबह 11 बजे अपने बेंगलुरु कार्यालय में पेश होने के लिए बुलाया था। यह उन्हें जारी किया गया दूसरा ऐसा नोटिस था, पहला 3 जनवरी को जारी किया गया था, जिसमें उन्हें 9 जनवरी को पेश होने का निर्देश दिया गया था। हालांकि, उन्होंने अपनी उम्र और संबंधित दस्तावेज जुटाने के लिए अतिरिक्त समय की आवश्यकता का हवाला देते हुए समय बढ़ाने की मांग की थी। 27 जनवरी को न्यायालय ने समन पर अंतरिम रोक लगा दी थी। 5 फरवरी को कर्नाटक हाई कोर्ट ने ईडी के समन पर रोक को 20 फरवरी तक बढ़ा दिया, जिससे पार्वती और सुरेश दोनों को राहत मिली थी। यह मामला मुडा द्वारा भूमि आवंटन में कथित अनियमितताओं से जुड़ा है, जिसमें ईडी धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के संभावित उल्लंघन की जांच कर रही है। पिछले साल कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने कर्नाटक के सीएम के खिलाफ मैसूर में 14 आवासीय स्थलों के आवंटन में भ्रष्टाचार की शिकायतों पर जांच की अनुमति दी थी। सिद्धारमैया और कांग्रेस पार्टी ने आरोपों से इनकार किया था। कर्नाटक लोकायुक्त पुलिस ने फरवरी में एमयूडीए भूखंड आवंटन मामले में अदालत को 11,000 पन्नों की अंतिम रिपोर्ट सौंपी थी। यह घटनाक्रम कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया को लोकायुक्त पुलिस द्वारा दी गई क्लीन चिट के आधिकारिक रूप से सार्वजनिक होने के एक दिन बाद हुआ था। सिद्धरमैया, उनकी पत्नी, साले बी एम मल्लिकार्जुन स्वामी, देवराजू और अन्य को मैसूर स्थित लोकायुक्त पुलिस प्रतिष्ठान द्वारा 27 सितंबर को दर्ज की गई प्राथमिकी में नामजद किया गया था।

'काशी और अयोध्या के बाद अब मथुरा की बारी'

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा अब मथुरा और ब्रज भूमि के विकास का समय आ गया

वृंदावन (एजेंसी)। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को कहा कि काशी और अयोध्या के कायाकल्प के बाद अब मथुरा और ब्रज भूमि के विकास का समय आ गया है। योगी ने आश्वासन दिया कि मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, नंदगांव, गोवर्धन और बलदेव सहित ब्रज क्षेत्र में अयोध्या, वाराणसी और प्रयागराज के परिवर्तन के समान तेजी से विकास होगा। बरसाना में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने श्री लाडली जी महाराज मंदिर में दर्शन-पूजन किया और फूलों एवं लड्डूमार होली के जरिए रंगोत्सव की शुरुआत की। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि पांच हजार साल से भारत की सनातन संस्कृति को ऊर्जा देने वाली यह ब्रज भूमि श्रद्धा एवं आस्था की धरा है। इसके कण-कण में श्री राधा और श्री कृष्ण के दर्शन होते हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा, उत्तर प्रदेश का सौभाग्य है कि यहां काशी, अयोध्या और मथुरा, ये तीनों तीर्थ स्थल सनातन एकता का प्रतीक के रूप में मौजूद हैं। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विरासत और विकास की नई परंपरा स्थापित हुई है, जिसका परिणाम हाल ही में संपन्न प्रयागराज महाकुंभ के भव्य आयोजन के रूप में देखने को मिला।

उन्होंने कहा, जो जितना सनातन धर्म के खिलाफ बोलता था, अफवाह फैलाता था और तर्कहीन बातें करता था, उन्हें सनातन धर्मावलंबियों ने महाकुम्भ के जरिए करारा जवाब दिया है। महाकुम्भ सनातन धर्म का दुर्लभतम क्षण बन गया है। सीएम योगी ने होली को एकता का सूत्र बताते हुए कहा कि होली आपसी सद्भाव और दूरियों को मिटाने का त्योहार है। महाकुम्भ ने जहां दुनिया को एकता का संदेश दिया, वहीं होली इसे और मजबूत करती है। उन्होंने बरसाना की विश्व प्रसिद्ध लट्ठमार होली और लड्डू मार होली का जिक्र करते हुए सनातन धर्म की अद्भुत परंपराओं की सराहना की।

मुख्यमंत्री ने कहा, इस बार के बजट में ब्रज भूमि के विकास के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि करोड़ों की योजनाओं के साथ बरसाना को विकास से जोड़ा जा रहा है। पहली बार बरसाना में रोपवे की सुविधा शुरू हुई है।

'यौन इच्छा के बिना नाबालिग के होठों को दबाना, छूना और साथ में सोना पॉक्सो के तहत अपराध नहीं'

दिल्ली (एजेंसी)। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि यौन प्रेरित प्रयासों के बिना नाबालिग लड़की के होठों को छूना और दबाना तथा उसके बगल में सोना पॉक्सो अधिनियम के तहत 'गंभीर यौन उत्पीड़न' नहीं है। इसके लिए आरोपी के खिलाफ अभियोजन चलाया जाए। जज स्वर्णकांता शर्मा ने कहा कि ये कृत्य नाबालिग की गरिमा का उल्लंघन और उसे ठेस पहुंचा सकते हैं, लेकिन 'प्रकट या यौन इरादे की मंशा' के बिना पॉक्सो अधिनियम की धारा 10 के तहत आरोप तय करने के लिए आवश्यक वैधानिक सीमा को पूरा करना मुश्किल होगा। जज ने अपने फैसले में कहा कि प्रथम दृष्ट्या भारतीय दंड संहिता की धारा 354 के तहत 'महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग' करने का स्पष्ट मामला बनता है। कोर्ट ने 24 फरवरी को 12 वर्षीय नाबालिग लड़की के चाचा की उस याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया, जिसमें उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 354 और पॉक्सो अधिनियम की धारा 10 के तहत आरोप तय किए जाने के खिलाफ दलील दी गई थी। कोर्ट ने धारा 354 के तहत आरोप बरकरार रखा, लेकिन पॉक्सो अधिनियम की धारा 10 के तहत उसे बरी कर दिया। शीर्ष अदालत के फैसलों का हवाला देते हुए कोर्ट ने कहा कि न्यायालय ने बार-बार कहा है कि आईपीसी की धारा 354 के संदर्भ में महिला की गरिमा की व्याख्या किसी महिला या नाबालिग लड़की की गरिमा और शरीर पर उसके अधिकार के सदर्भ में की जानी चाहिए।

कार्य में लापरवाही के चलते तीन अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस, एक अधिकारी निलंबित

मीडिया ऑडीटर, भोपाल (एजेंसी)। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के भोपाल वृत्त के उप महाप्रबंधक भेरूंदा श्री राजेश अग्रवाल,ललरिया वितरण केंद्र के मैनेजर श्री सुशील वर्मा और लाड़कुई वितरण केन्द्र के जूनियर इंजीनियर श्री पंकज कटियार को लापरवाही और कार्य के प्रति सजग नहीं रहने के आरोप में कारण बताओं नोटिस जारी किया गया है। इसी तरह गुनगा के जूनियर इंजीनियर श्री नितेश पलारिया को निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई भोपाल ग्रामीण वृत्त की समीक्षा बैठक के दौरान मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध संचालक श्री क्षितिज सिंघल ने की। प्रबंध संचालक श्री सिंघल ने समीक्षा बैठक के दौरान स्पष्ट संदेश दिया की बिलिंग एफिशिएंसी (दक्षता) तथा कलेक्शन एफिशिएंसी में कमी को किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि खराब तथा जले मीटर बदलें और उपभोक्ताओं को दी जा रही बिजली की प्रत्येक यूनिट बिक्रित यूनिट में परिवर्तित होना चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने किसानों को 5 रूपये में दिए जा रहे स्थाई पंप कनेक्शन के बारे में कहा कि इसके अंतर्गत अधिक से अधिक कृषकों को कनेक्शन प्रदान करें और जहां नियमित कनेक्शन देने की कार्रवाई में अड़चन आ रही है, वहां अस्थायी कनेक्शनन अवश्य प्रदान करें। प्रबंध संचालक श्री सिंघल ने मार्च माह का टारगेट देते हुए कहा कि मार्च माह में ग्रामीण वितरण केन्द्रों में कम से कम कुल उपभोक्ताओं की तुलना में 15 प्रतिशत नए कनेक्शन देकर नए उपभोक्ताओं को विद्युत प्रणाली से जोड़ा जाए। उन्होंने कहा की सकल तकनीकी एवं वाणिज्यक हानियों को न्यूनतम स्तर पर लाने के लिए मीटरिंग, बिलिंग और कलेक्शन को बढ़ाया जाए। उन्होंने कहा कि इस वित्तीय वर्ष के बाद अप्रैल माह में भोपाल ग्रामीण वृत्त में कार्यरत बिजली कार्मिकों की परफॉर्मेंस की समीक्षा कर उन्हें भविष्य में पदस्थापनाएं दी जाएंगी। इसलिए जो बेहतर कार्य करने वाले कार्मिक होंगे उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा वहीं नॉन परफॉर्मर कार्मिकों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।

मार्च माह में अवकाश दिनों में बिजली बिल भुगतान केन्द्र खुलेंगे

मीडिया ऑडीटर, भोपाल (एजेंसी)। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत शनिवार, 9 मार्च रविवार, 14 मार्च होली, 15 मार्च शनिवार, 16 मार्च रविवार, 19 मार्च रंगपंचमी, 22 मार्च शनिवार, 23 मार्च रविवार तथा 31 मार्च ईद-उल-फितर को बिल भुगतान केन्द्र सामान्य कार्य दिवसों की तरह कार्य करते रहेंगे। भोपाल शहर वृत्त के अंतर्गत चारों शहर संभाग यथा पश्चिम, पूर्व, दक्षिण तथा उत्तर संभाग के अंतर्गत सभी जोनल कार्यालय और दानिश नगर, मिसरोद, मण्डीदीप में बिल भुगतान केन्द्र उक्त अवकाश के दिन भी सामान्य कार्य दिवस की तरह खुले रहेंगे। बिजली उपभोक्ताओं से अपील है कि वे राजधानी के जोनल आफिस में पीओएस मशीन से कैश तथा ऑनलाइन भी बिल भुगतान कर सकते हैं। कंपनी ने यह भी निर्देश दिए हैं कि कंपनी कार्य क्षेत्र के सभी 16 जिलों में बिजली वितरण केन्द्र/बिल भुगतान केन्द्र अवकाश के दिनों में खुले रहेंगे। इसके लिए सभी मैदानी महाप्रबंधकों को निर्देशित किया गया है।

आईईएस पब्लिक स्कूल में युवा संसद का आयोजन

मीडिया ऑडीटर, भोपाल (एजेंसी)। भोपाल के आईईएस पब्लिक स्कूल में कुंजीलाल दुबे संसदीय विद्यापीठ के सहयोग से युवा संसद का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य छात्रों में लोकतांत्रिक मूल्यों और नेतृत्व क्षमता का विकास करना था। कार्यक्रम में छात्रों ने संसदीय कार्यवाही का अनुकरण किया। उन्होंने शिक्षा सुधार, महिला सुरक्षा, पर्यावरण नीतियां और डिजिटल परिवर्तन जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विचार-विमर्श किया। 12वीं कक्षा की छात्रा नमामी शर्मा ने अध्यक्ष की भूमिका निभाई। कार्यक्रम में पूर्व उपसचिव एमपी विधानसभा सचिवालय के के.एल. दलवानी मुख्य अतिथि थे। मध्य प्रदेश शासन संसदीय कार्य विभाग के अवर सचिव रवनीश तिवारी और डायरेक्टरेट ऑफ़ पब्लिक इंस्ट्रक्शन्स के असिस्टेंट डायरेक्टर राजेश्वर नाथ पाठक भी उपस्थित रहे। अतिथियों ने छात्रों की तर्कशक्ति और शासन की समझ की सराहना की। आईईएस पब्लिक स्कूल की ग्रुप डायरेक्टर मनीषा कवठेकर ने कहा कि यह आयोजन छात्रों में महत्वपूर्ण सोच और सार्वजनिक वक्तृत्व कौशल को बढ़ावा देता है। यह उन्हें वास्तविक जीवन की चुनौतियों के लिए तैयार करता है। उन्होंने सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया।

श्रीनाथजी की 265 साल पुरानी हवेली में होली का रंग

भोपाल। भोपाल के श्रीजी मंदिर में 40 दिवसीय होली उत्सव का आगाज हो गया है। प्रभु श्रीनाथजी और लाडले लाल नवनीत प्रिया जी को फिरोजी वस्त्र पहनाकर सेहरे से श्रृंगार किया गया। उत्सव में गुलाल, अबीर, चोवा और चंदन के साथ सात रंगों की गुलाल से होली खेली गई। संध्या समय में महिलाओं ने फाग रसिया गाते हुए 80 किलो गुलाब के फूलों से होली खेली। मंदिर के मुखिया श्रीकांत शर्मा के अनुसार, यह परंपरा 265 वर्षों से अनवरत चल रही है।

जीआईएस-भोपाल से मध्यप्रदेश बन रहा हेल्थकेयर, फार्मा और मेडिकल डिवाइसेज में निवेश का नया केंद-मुख्यमंत्री

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि मध्यप्रदेश की अनुकूल नीतियां, विकसित अधोसंरचना और मेडिकल डिवाइस पार्क जैसी सुविधाएं राज्य को दवा कंपनियों और चिकित्सा उपकरण निर्माताओं के लिए फेवरेट इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बना रही हैं। जीआईएस-भोपाल में हेल्थकेयर, फार्मा और मेडिटेक क्षेत्र की संभावनाओं पर व्यापक चर्चा हुई। विशेषज्ञों ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि मध्यप्रदेश चिकित्सा उपकरण निर्माण का प्रमुख केंद्र बनने की ओर अग्रसर है। उज्जैन में विकसित हो रहे 75 एकड़ के मेडिकल एवं फार्मास्यूटिकल पार्क को मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने वैश्विक निवेशकों के लिए 'बेस्ट डेस्टिनेशन' करार दिया।

जीआईएस-भोपाल में आयोजित 'मॉलिक्यूल्स-टू-मशीन (हेल्थकेयर, फार्मा, मेडिटेक)' सत्र के दौरान, विशेषज्ञों ने इस अवधारणा पर चर्चा करते हुए बताया कि मध्यप्रदेश दवा निर्माण से लेकर चिकित्सा उपकरण उत्पादन तक पूरे हेल्थकेयर इको सिस्टम को मजबूत कर रहा है। राज्य में फार्मास्युटिकल कंपनियों, एक्टिव

फार्मास्युटिकल इनग्रेडिएंट्स (एपीआई) निर्माण इकाइयों और मेडिकल डिवाइस विनिर्माण में तेजी से वृद्धि हो रही है।

एसोसिएशन ऑफ इंडियन मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री के समन्वयक श्री राजीव छिब्बर ने बताया कि उज्जैन स्थित विक्रम उद्योग नगरी में विकसित हो रहे मेडिकल डिवाइस पार्क में 23 विनिर्माताओं ने निवेश करने की पुष्टि की है। सरकार की नई औद्योगिक नीति के तहत दी जा रही रियायतों और सुविधाओं के कारण निवेशकों की इकाइयां स्थापित करने की लागत काफी कम हो रही है, जिससे निवेश को बढ़ावा मिल रहा है।

जीआईएस-भोपाल के शुभारंभ संबोधन में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मध्यप्रदेश को 'मेडिकल टेक्सटाइल्स' का प्रमुख केंद्र बताया। सर्जिकल गाउन, मास्क, पीपीई किट, सैनिटरी नैपकिन और अन्य उत्पादों के निर्माण में राज्य की अहम भूमिका को रेखांकित किया गया। कोविड महामारी में भारत ने मास्क और पीपीई किट के उत्पादन में वैश्विक पहचान बनाई थी, जिसे मध्यप्रदेश आगे बढ़ा रहा है।

मध्यप्रदेश देश के प्रमुख फार्मास्युटिकल राज्यों में से एक है। वर्तमान में प्रदेश में 270 से अधिक फार्मा कंपनियां कार्यरत हैं, जिनमें से 80 से अधिक पीथमपुर में स्थित हैं। राज्य में निर्मित दवाइयां 160 से अधिक देशों में निर्यात की जा रही हैं। प्रमुख निवेशकों में सनफार्मा, सिप्ला, लुपिन, एल्केंबिक, टॉरेंट फार्मा और एल्केमिस्ट जैसी दिग्गज कंपनियां शामिल हैं।

दो अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस और 3 फर्म ब्लैक लिस्टेड

भोपाल। लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रदेश में निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिये निर्माण कार्यों के औचक निरीक्षण की नवीन पहल प्रारंभ की गई हैं। इसमें हर माह की 5 और 20 तारीख़ को सॉफ्टवेयर के माध्यम से रैंडम तरीके से चयनित दलों, जिलों, निर्माण कार्यों और सामग्री के सैंपल लेने के स्थानों का औचक निरीक्षण किया जाएगा। गत दिवस लोक निर्माण विभाग के सातों परिक्षेत्रों के मुख्य अभियंताओं के सात दलों द्वारा सात जिलों में निरीक्षण किया गया। इस निरीक्षण के दौरान कुल 34 कार्यों को रैंडम आधार पर चयनित किया गया, जिनमें 14 कार्य पी.डब्ल्यू.डी. सड़क/ पुल, 10 कार्य पी.आई.यू., 8 कार्य म.प्र. सड़क विकास निगम तथा 2 कार्य म.प्र. भवन विकास निगम के अंतर्गत आए। निरीक्षण दलों से प्राप्त प्रतिवेदन की समीक्षा गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की गई। इस बैठक में श्री के.पी.एस. राणा, प्रमुख अभियंता (बी.एंड आर), प्रमुख अभियंता (भवन विकास निगम), उपसचिव लोक निर्माण विभाग, समस्त मुख्य अभियंता एवं निरीक्षणकर्ता अधिकारी उपस्थित रहे।राजगढ़ जिले के छापीखेड़ा-नलखेड़ा मार्ग में सबग्रेड कार्य में बड़े पत्थरों के उपयोग की गड़बड़ी पाए जाने पर कंसलटेंसी एवं एजीएम आरडीसी श्री अभिषेक गोकरू को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया तथा ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट किये जाने के निर्देश दिए गए। नरसिंहपुर जिले में करेली-सिंहपुर-डांगीढाना मार्ग में सीमेंट कांक्रीट में ज्वाइंट निर्माण में लापरवाही के कारण ओपन हो जाने की शिकायत मिली। इस पर ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट किये जाने के लिये मुख्य अभियंता को निर्देशित किया गया। बुरहानपुर जिले में धूलकोट शिवबाबा इटारिया एवं नरसिंहगढ़ शहरी क्षेत्र में कांक्रीट कार्य की धीमी गति को लेकर भी ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट किये जाने के निर्देश दिए गए।

धान की जगह वेयरहाउस में मिला भूसा,5 करोड़ रुपए की हेराफेरी के सबूत मिले

भोपाल। मध्य प्रदेश में धान उपार्जन समितियों में फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ ने 25 टीमों का गठन कर प्रदेशभर में कार्रवाई की। इन टीमों ने 12 जिलों की 150 उपार्जन समितियों और 140 वेयर हाउसेस की जांच की। अब तक की जांच में 19,910.53 क्विंटल धान की हेराफेरी पकड़ी गई है, जिससे शासन को करीब 5 करोड़ रुपए के नुकसान का अनुमान है। जानकारी के मुताबिक इस फर्जीवाड़े से हर साल शासन को करोड़ों की आर्थिक क्षति पहुंचती है। इस फर्जीवाड़े में उपार्जन समिति के पदाधिकारियों के अलावा कुछ ट्रांसपोर्टर, वेयर हाउस और राइस मिलें भी शामिल हो सकते हैं। इस तरह के घोटाले पर नियंत्रण करने के लिए प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश सीएम मोहन यादव ने पिछले दिनों ईओडब्ल्यू को दिए थे। इसके बाद ईओडब्ल्यू द्वारा 25 टीमें बनाकर प्रदेशव्यापी कार्रवाई की गई। बालाघाट, जबलपुर, डिंडोरी, रीवा, सतना, मैहर, सागर, पन्ना, ग्वालियर, नर्मदापुरम, नरसिंहपुर, श्योपुर इत्यादि 12 जिलों की 150 उपार्जन समितियों एवं 140 वेयर हाउसेस को चेक किया गया। सतना जिले के कनक वेयर हाउस में 535 क्विंटल धान के स्थान पर भूसी पाई गई। वेयर हाउस में सेवा सहकारी समिति पिंडरा एवं सेवा सहकारी समिति हिरौंदी जिला सतना द्वारा धान का भण्डारण किया गया है। कार्रवाई लगातार जारी है।

वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों ने विश्व धरोहर भीम बैटका का किया भ्रमण

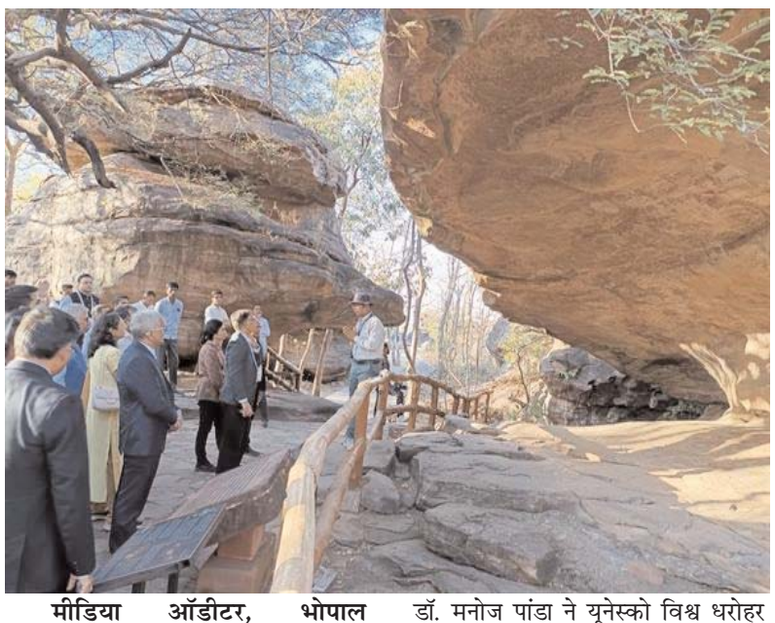

मीडिया ऑडीटर, भोपाल (एजेंसी)। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉ. अरविंद पनगढ़िया और सदस्य श्रीमती एनी जॉर्ज मैथ्यू, डॉ. सौम्य कांति घोष एवं डॉ. मनोज पांडा ने यूनेस्को विश्व धरोहर भीम बैटका का भ्रमण किया। उन्होंने प्रदेश की ऐतिहासिक और भारतीय संस्कृति की समृद्ध धरोहर को नजदीक से देखा। वित्त आयोग के सदस्यों ने कहा कि भीम बैटका जैसे ऐतिहासिक स्थल भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत के अमूल्य प्रतीक हैं। इन स्थलों का संरक्षण भावी पीढ़ियों के लिए अत्यंत आवश्यक है। वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों द्वारा भीम बैटका में शैलाश्रय तथा शैलचित्रों का अवलोकन किया गया।

पुरा पाषाण काल से मध्य ऐतिहासिक काल तक यह स्थान मानव गतिविधियों का केंद्र रहा है। यहाँ के शैल चित्र मुख्यत: सामूहिक नृत्य, रेखांकित मानवाकृति, शिकार, पशु-पक्षी, युद्ध और प्राचीन मानव जीवन के दैनिक क्रियाकलापों से जुड़े हैं। चित्रों में प्रयोग किये गए खनिज रंगों में मुख्य रूप से गेरुआ, लाल और सफेद रंग का उपयोग किया गया है। आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों को भीम बैटका में प्रस्तावित रॉक आर्ट इको पार्क म्यूजियम के बारे में बताया गया। आयोग के सदस्यों को गाइड रवि यादव द्वारा शैलाश्रयों तथा शैलचित्रों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।

मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह योजना विधवा जीवन में नव संचार का है माध्यम -सामाजिक न्याय मंत्री कुशवाह

मीडिया ऑडीटर, भोपाल (एजेंसी)। सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन कल्याण मंत्री श्री नारायण सिंह कुशवाह ने कहा है कि मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह योजना असमय विधवा हो चुकी बहनों के जीवन में नव-जीवन के संचार का माध्यम है। उन्होंने योजना के व्यापक प्रचार-प्रसार के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिए है। योजना में इस वित्त वर्ष में 709 कल्याणी बहनों को 14 करोड़ 18 लाख रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। योजना में गत वित्तीय वर्ष में 510 कल्याणी हितग्राहियों का आर्थिक सहायता प्रदान की गई थी। प्रमुख सचिव, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण श्रीमती सोनाली वायंगणकर ने बताया कि प्रदेश में निवासरत कल्याणियों (विधवा) को सामाजिक सुरक्षा प्रदान कर, नये जीवन की शुरूआत के लिए राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना संचालित की जा रही है। योजना में विवाह के बाद कल्याणी बहन को 2 लाख रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। उन्होंने बताया कि योजना का लाभ कल्याणी बहनें आसानी उठा सकें इसके लिए विभाग द्वारा कल्याणी विवाह पोर्टल बनाया गया। पोर्टल से योजनाओं की जानकारियाँ प्राप्त की जा सकती है। उन्होंने बताया कि योजना का लाभ उठाने के लिए आवश्यक है कि कल्याणी बहन और उनका जीवनसाथी मध्यप्रदेश के निवासी हो। विवाह के समय कल्याणी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष या उससे अधिक व कल्याणी के पति की आयु 21 वर्ष या उससे अधिक हो। कल्याणी आयकरदाता न हो तथा कल्याणी शासकीय कर्मचारी/अधिकारी न हो, किसी राज्य/केंद्र सरकार या शासन हित पोषित निगम, उपक्रम, संस्था के अधीन कार्यरत कर्मचारी/अधिकारी न हो।

विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधार के लिये राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रभावी क्रियान्वयन

मीडिया ऑडीटर, भोपाल (एजेंसी)। प्रदेश के विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिये राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 का क्रियान्वयन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा प्रभावी तरीके से किया जा रहा है।

नीति के क्रियान्वयन के लिये राज्य शासन द्वारा आयुक्त और संचालक स्तर की अध्यक्षता में वरिष्ठ अधिकारियों की 14 समितियाँ गठित की गयी हैं। यह समितियाँ राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विभिन्न ग्रुप और क्षेत्रों से संबंधित हैं। राज्य शासन ने स्कूल शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में टॉस्क फोर्स का गठन किया है। इसमें स्कूल शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी पदेन सदस्य हैं। समिति में शासकीय एवं अशासकीय शिक्षाविदों को भी शामिल किया गया है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति एवं क्रियान्वयन के लिये सदस्यों के बीच परिचर्चा भी करायी गयी है। इसमें अजीम प्रेमजी फाउण्डेशन के साथ समन्वय में विशेषज्ञ के उद्बोधन कराये गये हैं। उन्मुखीकरण के दौरान एनसीईआरटी के विभागाध्यक्ष द्वारा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फाउण्डेशनल (एनसीएफ) स्टेज विकास प्रक्रिया और राज्य पाठ्यचर्या फाउण्डेशनल (एससीएफ) स्टेज के बारे में भी जानकारी दी गयी है। केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के दिशा-निर्देश अनुसार न्यू एजुकेशन पॉलिसी (एनईपी) ट्रैकर को नियमित रूप से अपडेट किया जा रहा है।

राज्य में विशेष आवश्यकता वाले चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स (सीडब्ल्यूएसएन) 9550 नये बच्चों की पहचान एवं उनका कक्षा-9 से 12 में नामांकन सुनिश्चित किया गया है। इसी के साथ विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के शिक्षण के लिये प्रदेश में 8500 शिक्षकों को वर्ष 2024 में 2 सत्रों में विशेष प्रशिक्षण भी दिलाया गया है। सभी विकासखण्डों में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा संसाधन केन्द्र विकसित किये गये हैं।

नई शिक्षा नीति में विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा देने पर जोर दिया गया है। प्रदेश में 2383 विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा संचालित की जा रही है। इनमें करीब 4 लाख विद्यार्थियों का इनरोलमेंट किया गया है और उन्हें 14 ट्रेड में व्यावसायिक शिक्षा देने की व्यवस्था की गयी है। प्रदेश के 798 हायर सेकेण्डरी विद्यालयों में कृषि संकाय और 465 हायर सेकेण्डरी स्कूलों में कृषि ट्रेड संचालित किये जा रहे हैं। स्टार्स प्रोजेक्ट के अंतर्गत 100 विद्यालयों में नियमित छात्रों के साथ-साथ ड्रॉपआउट विद्यार्थियों की भी व्यावसायिक शिक्षा प्रारंभ की गयी है। प्रदेश के प्रत्येक सीएम राइज विद्यालय में 2 वोकेशनल ट्रेड्स के लिये लैब निर्मित की जा रही है। विभाग के 52 सीएम राइज विद्यालयों में रोबोटिक्स लैब की स्थापना भी करायी गयी है।

नेमावर में जल प्रदाय परियोजना का कार्य प्रगति पर

मीडिया ऑडीटर, भोपाल (एजेंसी)। नगरीय विकास एवं आवास विभाग के उपक्रम, मध्यप्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कम्पनी द्वारा देवास जिले के नेमावर में जल प्रदाय परियोजना का कार्य तेजी से किया जा रहा है। इस परियोजना के तहत नेमावर क्षेत्र में शुद्ध जल आपूर्ति के लिए अत्याधुनिक जल शोधन संयंत्र का निर्माण किया जा रहा है। परियोजना की लागत लगभग 21 करोड़ रूपये है। नेमावर में जल को शुद्ध करने के लिए 2.21 मिलियन लीटर प्रति दिन (एमएलडी) क्षमता का जल शोधन संयंत्र निर्माणाधीन है। यह संयंत्र क्षेत्र की जल आपूर्ति व्यवस्था को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसके अलावा, जल के संग्रहण के लिए 100 किलोलीटर और

500 किलोलीटर क्षमता के दो ओवरहेड टैंक भी बनाये जा रहे है। इनका निर्माण तेज गति से चल रहा है। नेमावर के साथ-साथ खातेगांव नगर परिषद क्षेत्र में नर्मदा जल की आपूर्ति के लिए नर्मदा तट पर नवीन इंटेक वेल का निर्माण भी तेज गति से जारी है। प्रत्येक घर तक शुद्ध जल पहुँचाने के लिए लगभग 37 किलोमीटर लंबी जल वितरण लाइन बिछाई जा रही है, जिसमें से अब तक 13 किलोमीटर पाइप लाइन बिछाई जा चुकी है। इस योजना से करीब 1200 घरों को नल जल कनेक्शन दिए जाने हैं। इनमें से 576 घरों को कनेक्शन दिये जा चुके है। इस परियोजना के पूरा होने के बाद नेमावर के लगभग 6 हजार से अधिक निवासियों को शुद्ध और सुरक्षित जल की आपूर्ति होगी।

नेमावर परियोजना को एशियन डेवलपमेंट बैंक की सहायता पूरा किया जा रहा है। परियोजना के संचालन और संधारण के साथ इसकी कुल लागत लगभग 21 करोड़ रुपये है। परियोजना के पूरा होने के बाद, नेमावर के निवासियों को शुद्ध जल की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित होगी, जो उनके स्वास्थ्य और जीवन स्तर में सुधार लाएगी।

पति ने पत्नी को कुल्हाड़ी मारी, मौत

फिर खुद ने फांसी लगाकर दी जान, नशा करने से रोकने पर किया था विवाद

मीडिया ऑडीटर, सीधी (निप्र)। सीधी में पति ने पत्नी की कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी। उसने गर्दन पर एक के बाद एक 5 वार किए। इसके बाद खुद ने भी फांसी लगाकर जान दे दी। घटना शुक्रवार सुबह 9 से 10 बजे के बीच जिला मुख्यालय से 42 किलोमीटर दूर बहरी थाना क्षेत्र के सिहोलिया गांव की है। पत्नी ने पति को नशा करने से रोका था। इसी को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ।

मृतक अभय राज यादव (34) और इसकी पत्नी सविता यादव (30) के दो बच्चे हैं। अब बेटा मुन्ना यादव (8 साल) और रागनी यादव की (5 साल) है।

पत्नी ने नशा करने से रोका तो की हत्या: पड़ोसी ने नाम ना बताने की शर्त पर यह बताया कि पति और पत्नी के बीच अक्सर झगड़े होते थे। हाल ही में 5 दिन पहले अभी पति ने पत्नी को बुरी तरह से पीटा था। पति अभय राज यादव नशे का आदी था। वह मुंबई में दीवार पेंटिंग का काम करता था। वह अक्सर गांजा और कोरेक्स के साथ शराब का नशा करता था। पत्नी इसका विरोध हरदम किया करती थी और आज भी झगड़ा इसी वजह से हुआ था। जहां पत्नी ने नशा करके घर आने से मना किया तो उसने कुल्हाड़ी से हमला कर दिया।

मौके पर पहुंची पुलिस: ग्रामीणों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों शवों को कब्जे में लिया। दोनों शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही जांच भी शुरू कर दी है।

एसपी डॉक्टर रविंद्र वर्मा ने बताया कि खुद में भी मौके पर पहुंचा था। पुलिस से पूरे एंगल से जांच कर रही है।

जन अभियान परिषद द्वारा चयनित आदर्श ग्राम मरसरहा मे समग्र ग्राम विकास की अवधारणा पर हुआ संवाद

मीडिया ऑडीटर, सीधी (निप्र)। मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद से संबद्ध नवांकुर संस्था गीतांजलि जन कल्याण समिति जमुआर द्वारा ग्राम विकास प्रस्फुटन समिति मरसरहा सेक्टर क्रमांक 5 कुंवरी विकासखंड सिहावल जिला सीधी के आदर्श ग्राम मरसरहा में ग्राम विकास प्रस्फुटन समिति कार्यालय में मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग मध्य प्रदेश शासन के जिला समन्वयक शिवदत्त उर्मलिया के मुख्य आतिथ्य, ग्राम पंचायत मर्सरहा के सरपंच कल्पना रावत के अध्यक्षता एवं विकासखंड समन्वयक अनिल पाठक के विशिष्ट आतिथ्य मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद द्वारा संचालित मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास कार्यक्रम के परामर्शदाता गोविंद प्रसाद गौतम नवांकुर संस्था गीतांजलि जन कल्याण समिति जमुआर के अध्यक्ष रविशंकर मिश्र एवं आदर्श ग्राम के सभी गणमान्य नागरिक की उपस्थिति में आदर्श ग्राम की परिकल्पना के संबंध में बैठक की गई।

नवांकुर संस्था अध्यक्ष रविशंकर मिश्र ने मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के बारे में सभी को जानकारी दी। साथ ही शासन द्वारा संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। इसके बाद विकास खंड समन्वयक द्वारा आदर्श ग्राम की परिकल्पना के बारे में जानकारी देते हुए बताया गया कि सभी योजनाओं को अंतिम छोर में बैठे व्यक्ति तक पहुंचाने में सहयोग करना।

इसके बाद मुख्य अतिथि शिव दत्त उर्मलिया ने कहा कि गांव के सभी मोहल्लों में संस्कार केंद्र शुरू कर बच्चो के शिक्षा स्तर में सुधार करने ,स्वच्छता के क्षेत्र में सभी को अपने शरीर के साथ आस पास के वातावरण की भी सफाई आवश्यक है और सभी लोग शौचालय का प्रयोग करें , जल संरक्षण के लिए ग्राम के अंदर जन सहयोग से सभी हैंड पंपों के पास सोक्ता गड्ढ़ा बनाए और नदी नालों में बोरी बंधान का जल संरक्षण करने का कार्य करें,ग्राम में हर व्यक्ति को साक्षर करने और ग्राम में बच्चो में होने वाले कुपोषण को दूर करने हेतु कमजोर एवं कुपोषित बच्चों को आंगनबाड़ी, आशा, एएनएम के द्वारा जांच कराकर पोषण पुनर्वास केंद्र में भेजकर उचित पोषण और चिकित्सा दिलाकर कुपोषण दूर करें, साथ ही ग्राम में बचनालय स्थापित कर धार्मिक एवं सामान्य ज्ञान की पुस्तक रखे जिससे ग्रामीण जन लाभ उठा सके। इसके बाद मुख्य अतिथि ने पौधारोपण में आम के पौधे का रोपण किया गया। अंत में गांव में जागरूकता रैली निकाली गई। इसके बाद प्रस्फुटन समिति अध्यक्ष राजेश सिंह द्वारा सभी अतिथियों का आभार और धन्यवाद व्यक्त किया गया।

260 जोड़ों का सामूहिक विवाह हुआ

दूल्हा-दुल्हन को 55 हजार रुपए की मदद दी, अप्रैल में भी होगा सम्मेलन

मीडिया ऑडीटर, सिंगरौली (निप्र)। सिंगरौली के कन्या कॉलेज प्रांगण में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत 260 जोड़ों का सामूहिक विवाह हुआ। कार्यक्रम में सिंगरौली विधायक रामनिवास शाह, नगर निगम की महापौर रानी अग्रवाल और कलेक्टर चंद्रशेखर शुक्ला भी थे।

कलेक्टर शुक्ला ने बताया कि योजना की शुरुआत में जोड़ों को 5000 रुपए दिए जाते थे। महंगाई बढ़ने के कारण अब यह राशि बढ़ाकर 55,000 रुपए कर दी गई है। उन्होंने यह भी बताया कि अप्रैल में दूसरा सामूहिक विवाह होगा।

विधायक रामनिवास शाह ने कहा कि यह योजना उन लोगों के लिए है जो बेटी की शादी का खर्च नहीं उठा सकते। उन्होंने कहा कि सक्षम परिवार भी, जो आडंबर से दूर रहना चाहते हैं, इस योजना का लाभ ले सकते हैं।

कार्यक्रम में शादी करने वाली एक दुल्हन बुलबुल साकेत ने बताया कि उनके परिवार वाले उनकी पसंद के लड़के से शादी के लिए राजी नहीं थे। इसलिए उन्होंने अपने पति सूरज कुमार के साथ इस योजना के तहत विवाह किया।

जन औषधि केंद्र प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी परियोजना है : सांसद

सस्ती दरों पर जीवन रक्षक दवाइयां उपलब्ध कराना जन औषधि केंद्र का लक्ष्य : सांसद

मीडिया ऑडीटर, सीधी (निप्र)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी परियोजना प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र मध्य प्रदेश के सभी जिला केंद्रो पर भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा संचालित है। प्रधानमंत्री की मंशा है कि उच्च गुणवत्ता की जीवन रक्षक दवाइयां सस्ती दरो पर आम लोगों को सरल और सहज ढंग से उपलब्ध हो, जिसके लिए हमारे प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र कार्य कर रहे हैं। जन औषधि के माध्यम से लोगों ने लगभग 30 हजार करोड़ रुपए से अधिक की बचत की है। उक्त बातें सांसद और भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के चेयरमैन डॉ राजेश मिश्रा ने भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा संचालित जिला चिकित्सालय परिसर में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र के निरीक्षण के दौरान कहीं।

सांसद डॉ राजेश मिश्रा ने जन औषधि दिवस पर जन औषधि केंद्र का निरीक्षण करते हुए आम लोगों के साथ-साथ विभिन्न रोगों के रोग विशेषज्ञ चिकित्सक, नर्स एवं जन औषधि केंद्र के लाइसेंसी सुरेंद्र मणि दुबे और फार्मासिस्ट डा अनुपमा त्रिपाठी से चर्चा की।

सांसद डॉ राजेश मिश्रा ने कहा कि जन औषधि केंद्र जिले के विभिन्न विकासखंडों में संचालित हो, इसके लिए हम कार्य कर रहे हैं। अत्यंत कम समय में कुसमी ब्लाक में जन औषधि केंद्र का भव्य शुभारंभ होने वाला है। सांसद ने कहा कि जन औषधि केंद्र में जीवन रक्षक दवाइयां बाजार मूल्य से पचासी प्रतिशत तक से भी कम मूल्य पर यहां उपलब्ध है।

सांसद ने जन औषधि दिवस पर शुभकामनाएं देते हुए कहा कि जिले के लोग जन औषधि केंद्र का पूरा-पूरा लाभ लें और अपनी खून पसीने की कमाई की बचत करें।

निरीक्षण के दौरान देव कुमार सिंह चौहान, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ बबीता खरे, सिविल सर्जन डॉ दीपा रानी इसरानी, डॉ सुनीता तिवारी, डॉ हिमेश पाठक, डॉ रवि शंकर पटेल, डीपीएम पुष्पेंद्र शुक्ला, नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष देवेंद्र सिंह मुन्नू, डॉ विक्रम सिंह चौहान, प्रमोद द्विवेदी, मिट्ठू केवट, पंकज पाण्डेय, मुनिराज विश्वकर्मा, डॉ मनोज सिंह परिहार, तुषार द्विवेदी, अवनीश मिश्र, प्रकाश पाण्डेय, कौशलेंद्र सिंह, अभय सिंह, पुनीत त्रिपाठी, पुष्पेंद्र मिश्रा सहित चिकित्सक और गणमान्य जन उपस्थित रहे।

कार की टक्कर से बुलेट सवार युवक की मौत

गमी कार्यक्रम से लौट रहा था अनूपपुर का युवक, रीवा-शहडोल मार्ग पर हादसा

मीडिया ऑडीटर, शहडोल (निप्र)। शहडोल में शुक्रवार दोपहर 3.30 बजे ब्यौहारी थाना क्षेत्र के जेल तिराहे पर कार की टक्कर से बुलेट सवार युवक की मौत हो गई। बाइक रीवा से शहडोल की ओर आ रही थी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे के समय युवक ने हेलमेट पहन रखा था।

घटना के बाद शहडोल-रीवा मार्ग पर कुछ देर यातायात प्रभावित रहा। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर क्षतिग्रस्त वाहनों को हटवाया और यातायात बहाल किया। मृतक के शव को पोस्टमॉर्टम के लिए अस्पताल भेजा।

थाना प्रभारी अरुण पांडे के मुताबिक, मृतक अनूपपुर जिले का रहने वाला था। वह रीवा में एक गमी कार्यक्रम में शामिल होकर घर लौट रहा था।

12 वी कक्षा के भूगोल विषय में शामिल हुए 6135 विद्यार्थी

जिले में संचालित है शांति पूर्ण परीक्षा

मीडिया ऑडीटर, सीधी (निप्र)। माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित हायर सेकेण्डरी बोर्ड के भूगोल विषय की परीक्षा 07 मार्च को जिले के 64 परीक्षा केन्द्रो में आयोजित हुई जिसमें जिले में कुल दर्ज 6250 छात्रों में से कुसमी में 616, मझौली में 957, रामपुर नैकिन में 1268, सिहावल में 1408 कुल 6135 विद्यार्थी परीक्षा में उपस्थित रहे, 115 विद्यार्थी परीक्षा में शामिल नहीं हुये। परीक्षा की सुचिता बनाये रखने के लिए कलेक्टर स्वारोचिष सोमवंशी द्वारा गठित पैनल डॉ पी एल मिश्र जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा उपनी, कुचवाही, रजडिहा, सपही का निरीक्षण किया गया। प्रवीण शुक्ला द्वारा ए.डी.पी.सी. रमसा द्वारा परीक्षा केन्द्र भरतपुर, अमिलई, बघवार का निरीक्षण किया गया। एपीसी रमसा डॉ सुजीत कुमार मिश्र द्वारा भदौरा, टमसार, उत्कृष्ट कुसमी और कमछ का निरीक्षण किया गया। नागेन्द्र सिंह जिला आपूर्ति अधिकारी द्वारा सपही, पोखरा, तरका, बहरी का निरीक्षण किया गया।

विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी सीधी द्वारा सी.एम.राईज कन्या सीधी, गणेश अमहा का निरीक्षण किया गया। विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी मझौली द्वारा ताला, उत्कृष्ट मझौली, कन्या मझौली, मॉडल मझौली का निरीक्षण किया गया। विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी सिहावल द्वारा हटवाखास, सुडवार का निरीक्षण किया गया। विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी रामपुर नैकिन द्वारा उत्कृष्ट रामपुर नैकिन, मॉडल रामपुर नैकिन का निरीक्षण किया गया। पी.के. पाण्डेय कलेक्टर पैनल द्वारा उत्कृष्ट कुसमी, पोडी बस्तुआ, कमछ का निरीक्षण किया गया।

कन्ट्रोल रूम प्रभारी रामकृष्ण तिवारी ने जानकारी देते हुये बताया कि जिले में परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके एवं व्यवस्थित रूप से संचालित है। जिले किसी भी परीक्षा केन्द्र में बाहरी दबाव नही है। नकल प्रकरण निरंक है।

नेशनल लोक अदालत का आयोजन 08 मार्च को

20 खंडपीठों द्वारा होगा प्रकरणों का निराकरण

मीडिया ऑडीटर, सीधी (निप्र)। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशानुसार वर्ष 2025 की प्रथम लोक अदालत का आयोजन शनिवार दिनांक 08 मार्च को जिला मुख्यालय सीधी तथा तहसील चुरहट, मझौली एवं रामपुर नैकिन में किया जायेगा। जिला मुख्यालय सीधी में प्रातः 10:30 बजे स्थानीय ए.डी.आर. भवन जिला न्यायालय परिसर में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीधी के अध्यक्ष प्रयाग लाल दिनकर द्वारा नेशनल लोक अदालत का शुभारंभ किया जायेगा।

08 मार्च को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में प्रकरणों के निराकरण हेतु 20 न्यायिक खंडपीठों का गठन किया गया है। जिला न्यायालय सीधी में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रयाग लाल दिनकर, द्वितीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनीष कुमार श्रीवास्तव, प्रथम जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार श्रीवास्तव, चतुर्थ जिला एवं सत्र न्यायाधीश गौतम कुमार गुजरे, प्रथम जिला न्यायाधीश सीधी के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश उर्मिला यादव, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट लक्ष्मण डोडवे, न्यायिक मजिस्ट्रेट रेनू श्रीवास्तव, न्यायिक मजिस्ट्रेट सोनू जैन, न्यायिक मजिस्ट्रेट सरिता चौधरी, न्यायिक मजिस्ट्रेट कपिल देव काछी, न्यायिक मजिस्ट्रेट मृदुल लटौरिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट अभिषेक साहू, एवं श्रम न्यायालय के प्रकरणों का निराकरण हेतु श्रम न्यायाधीश सुशील गहलोत की न्यायिक खंडपीठ का गठन किया गया है। सिविल न्यायालय चुरहट में न्यायिक मजिस्ट्रेट नृपेन्द्र सिंह परिहार, न्यायिक मजिस्ट्रेट वैशाली बडेरिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट विजया विश्वकर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट राहुल त्रिपाठी एवं सिविल न्यायालय मझौली में न्यायिक मजिस्ट्रेट रूची परते तथा सिविल न्यायालय रामपुर नैकिन में न्यायिक मजिस्ट्रेट परमानंद सनोडिया तथा न्यायिक मजिस्ट्रेट अरहम खान की खंडपीठों का गठन किया गया है।

पुलिस को देखकर ट्रैक्टर लेकर भागे, पलटा, चालक और मालिक फरार

मीडिया ऑडीटर, शहडोल (निप्र)। खैरहा थाना क्षेत्र में शुक्रवार को छपरी घाट सरफा नदी से रेत का अवैध उत्खनन और परिवहन की सूचना पर थाना प्रभारी दिलीप सिंह अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस को देखते ही ट्रैक्टर चालक वाहन लेकर भागने लगा। भागते समय उसने हाइड्रोलिक उठाकर रेत को रास्ते में ही गिरा दिया। जंगल के रास्ते भागते समय ट्रैक्टर बेकाबू होकर गड्ढे में पलट गया। हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ।

पुलिस की जांच में सामने आया कि ट्रैक्टर चालक मुकेश कोल और वाहन मालिक विपिन द्विवेदी बोडरी गांव के निवासी हैं। दोनों मौके से फरार हो गए। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ खनिज अधिनियम और शासकीय कार्य में बाधा डालने की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस ने ट्रैक्टर को जब्त कर थाने में खड़ा करवा दिया है। दोनों फरार आरोपियों की तलाश जारी है।

दो दिन से लापता युवक-युवती के शव नहर में मिले

हादसा, आत्महत्या और हत्या के एंगल से पुलिस कर रही जांच

मीडिया ऑडीटर, सीधी (निप्र)। सीधी जिले में शुक्रवार सुबह करीब 10: 30 बजे झगरौही के पास बाणसागर नहर में एक युवक और युवती के शव मिले।

कमर्जी थाने की पुलिस के मुताबिक, चरवाहा सत्यवान साकेत ने शवों को देखा और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने शवों की पहचान की। मृतक युवक मुबारक अली ग्राम गेरुआ, थाना अमिलिया का रहने वाला था। युवती खुशबू निशा ग्राम खोरबा खास की थी।

पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवों को नहर से निकाला। पुलिस पंचनामे की कार्रवाई के बाद शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है। अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि दोनों वहां कैसे पहुंचे।

लोगों के मुताबिक दोनों एक-दूसरे को जानते थे। पुलिस मामले की जांच कर रही है। यह हादसा था या आत्महत्या या कुछ और इन सभी पहलुओं की गहराई से पड़ताल की जा रही है। पुलिस परिजनों से भी पूछताछ कर रही है।

छात्रों ने प्रकृति को बचाने के लिए चलाई कलम

मीडिया ऑडीटर, रीवा (निप्र)। शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय में पर्यावरण संरक्षण पर आधारित प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें छात्राओं ने बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर देकर इस प्रतियोगिता में भाग लिया। इप्को भोपाल के द्वारा प्रायोजित, इको क्लब कन्या महाविद्यालय रीवा के द्वारा आयोजित इस अभियान में पर्यावरण जागरूकता, जल जागरुकता जैव विविधता संरक्षण एवं विभिन्न संसाधनों के सदुपयोग हेतु विभिन्न कार्यक्रम जिसमें कार्यशाला, प्रश्नोत्तरी, प्राकृतिक भ्रमण, प्रदर्शनी का आयोजन महाविद्यालय में आयोजित हो रहा है।

प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में प्राचार्य मेजर डॉ विभा श्रीवास्तव ने कहा की पर्यावरण संरक्षण प्राकृतिक पर्यावरण को विभिन्न मानवीय गतिविधियों से बचाने का अभ्यास है जो भविष्य की पीढ़ियों के लिए इसकी गुणवत्ता को खराब, नष्ट या कम कर देते हैं। पर्यावरण संरक्षण हाल के दशकों में एक व्यापक मुद्दा बन गया है क्योंकि पर्यावरण पर मानवीय दबाव तेजी से बढ़ गया है। पर्यावरण की रक्षा करने के कई तरीके हैं। पर्यावरण की रक्षा करने का एक तरीका है रीसाइकिलिंग - कार्बन फुटप्रिंट को कम करने और प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित करने का एक तरीका। यह लैंडफिल में जाने वाले कचरे की मात्रा को भी कम करता है, जिससे जल निकायों में कम प्रदूषण होता है।

दूसरा तरीका है अपने जीवन में पर्यावरण के अनुकूल उत्पादों का उपयोग करना। यह हवा, जमीन और पानी में हानिकारक रसायनों और विषाक्त पदार्थों की संख्या को कम करके एक स्वस्थ पर्यावरण में योगदान दे सकता है। वनस्पति शास्त्र विभाग की विभागाध्यक्ष डॉ राजश्री पाण्डेय ने कहा की पर्यावरण की रक्षा के लिए हमें इस बात के प्रति सचेत रहना चाहिए कि हम क्या खाते हैं और कैसे खाते हैं। हमारी हवा, पानी और ज़मीन की गुणवत्ता को कई कारक प्रभावित करते हैं, लेकिन पर्यावरण पर इसके प्रभाव को हमेशा ध्यान में रखते हुए छोटी शुरुआत करना सबसे अच्छा है।वनरोपण और वृक्षारोपण ग्लोबल वार्मिंग, मृदा अपरदन आदि को कम करके हमारे पर्यावरण की रक्षा करने में मदद करते हैं। हम गाड़ी चलाने के बजाय कारपूलिंग के माध्यम से अपने कार्बन पदचिह्न को कम कर सकते हैं, जो सस्ता है और हमारी ऊर्जा खपत और उत्सर्जन को कम करता है। प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में 500 छात्राओं ने हिस्सा लिया जिसमें छात्राओं को सहभागिता प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। इस आयोजन में कार्यक्रम संयोजक डॉ करुणा शंकर मिश्रा ने कार्यक्रम की रूपरेखा एवं एवं आगे के भ्रमण कार्यक्रम पर छात्रों को अवगत कराया एवं एप्को भोपाल के द्वारा चलाए जा रहे अभियान की रूपरेखा रखी। इस कार्यक्रम में इको क्लब नोडल डॉ इला तिवारी ने बच्चों के सहभागिता हेतु धन्यवाद व्यक्त किया। इस आयोजन इको क्लब के सदस्य डॉ राहुल रूपेश द्विवेदी डॉ अनुराधा मिश्रा डॉ अलका शुक्ला डॉ उमेश मिश्रा डॉ विकास पांडे सहित अन्य लोग उपस्थित रहे।

सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा सुगम्य यात्रा का आयोजन किया गया

मीडिया ऑडीटर, सीधी (निप्र)। सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा शुक्रवार 07 मार्च 2025 को सुगम्य यात्रा का आयोजन किया गया। इस यात्रा का उद्देश्य सार्वजनिक स्थलों पर दिव्यांगजनों के लिए सुगमता की उपलब्धता का निरीक्षण करना एवं आवश्यक सुधारों हेतु संबंधित विभागों को निर्देशित करना था। इस यात्रा को एसडीएम गोपद बनास नीलेश शर्मा एवं उपसंचालक सामाजिक न्याय अशोक तिवारी द्वारा हरी झंडी दिखाकर कलेक्ट्रेट परिसर से रवाना किया गया।

निरीक्षण दल ने गांधी स्कूल, गर्ल्स कॉलेज, संजय गांधी कॉलेज, बस स्टैंड, पुलिस अधीक्षक कार्यालय, नगरपालिका एवं सरस्वती स्कूल का दौरा किया। निरीक्षण में पाया गया कि गांधी स्कूल में रैंप की सुविधा उपलब्ध नहीं थी, जिससे दिव्यांग छात्रों को कठिनाई हो सकती है। इसी प्रकार गणेश स्कूल एवं गणेश कॉलेज में भी सुगमता से संबंधित आवश्यक सुधारों की जरूरत महसूस की गई। वहीं गर्ल्स कॉलेज एवं संजय गांधी कॉलेज में दिव्यांगजनों के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध पाई गईं।

बस स्टैंड निरीक्षण के दौरान यह सामने आया कि बसों में दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित सीटों पर कोई स्पष्ट संकेतक नहीं लगे थे और किराया सूची में दिव्यांगजनों को मिलने वाली रियायतों का उल्लेख नहीं था। इस कमी के कारण दिव्यांग यात्रियों को जानकारी के अभाव में असुविधा का सामना करना पड़ सकता है।

सुगम्य यात्रा का मुख्य उद्देश्य दिव्यांगजनों को सरकारी योजनाओं एवं सुविधाओं का लाभ सुगमता से प्राप्त कराने हेतु जागरूकता एवं आवश्यक सुधारों की पहल करना था। इस यात्रा के निष्कर्षों के आधार पर संबंधित विभागों को आवश्यक सुधार हेतु निर्देशित किया जाएगा, ताकि दिव्यांगजन बिना किसी बाधा के सार्वजनिक स्थलों एवं परिवहन सेवाओं का उपयोग कर सकें। निरीक्षण दल में प्रदीप द्विवेदी (सामाजिक सुरक्षा अधिकारी, नगरपालिका सीधी) नम्रता मिश्रा ए.ओ., शिवांसु शुक्ला पुनर्वास विशेषज्ञ स्पेशल एजुकेटर सम्मिलित रहे।

भारत में सैंडविच जेनरेशन के 60% लोगों को भविष्य की फाइनेंशियल सिक्योरिटी की चिंता

मीडिया ऑडीटर, सतना/रीवा (निप्र)। भारत में सैंडविच जेनरेशन के लोग अपने माता-पिता और बच्चों की ज़िंदगी को हर संभव तरीके से सबसे बेहतर बनाने पर ध्यान देते हैं, फिर भी उन्हें ऐसा लगता है कि वे अपने भविष्य के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं हैं। एडलवाइज लाइफ़ इंश्योरेंस की एक स्टडी के अनुसार, 60% उत्तरदाता इस बात से सहमत हैं कि, "चाहे मैं कितनी भी सेविंग या इन्वेस्ट कर लूँ, पर ऐसा लगता है कि ये भविष्य के लिए काफ़ी नहीं है।" सामान्य तौर पर 35 से 54 साल की उम्र के लोगों को सैंडविच जेनरेशन कहा जाता है, जिनके कंधों पर दो पीढ़ियों - यानी अपने बुज़ुर्ग माता-पिता और बढ़ते बच्चों की आर्थिक ज़रूरतों को पूरा करने की ज़िम्मेदारी होती है। जीवन बीमा कंपनी ने यू गोव के साथ मिलकर देश के 12 शहरों में इस जेनरेशन के 4,005 लोगों का एक सर्वे किया, ताकि उनके नज़रिये, उनकी धारणा और वित्तीय तैयारी के स्तर को समझा जा सके। इस मौके पर एडलवाइज लाइफ़ इंश्योरेंस के एमडी एवं सीईओ, सुमित राय ने कहा, "पिछले कुछ सालों में अपने ग्राहकों के साथ बातचीत के आधार पर हमने इस बात को करीब से जाना है कि, सैंडविच जेनरेशन के लोग किस तरह अपने माँ-बाप और बच्चों की देखभाल के बीच फंसे हुए हैं। वे स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा जैसी ज़रूरी सुविधाएँ उपलब्ध कराना चाहते हैं, साथ ही वे अरमानों भरी ज़िंदगी भी देना चाहते हैं, जिसमें 'ज़रूरतों' को पूरा करने के लिए 'ख़्वाहिशों' की कुर्बानी नहीं देनी पड़े। यही सबसे बड़ी वजह है, जो उन्हें वित्तीय फैसले लेने के लिए प्रेरित करती है। और इन सब के बीच, वे अक्सर अपने सपनों को पीछे छोड़ देते हैं, जिससे उन्हें यह महसूस होता है कि वे भविष्य के लिए तैयार नहीं हैं।" उनके वित्तीय फैसले परिवार के लिए अपनी ज़िम्मेदारी और प्यार पर आधारित होते हैं। हमारी स्टडी के नतीजे बताते हैं कि, इस जनरेशन के लोगों में आर्थिक रूप से तालमेल का अभाव या मनी डिस्मॉर्फिया है। 50% से अधिक लोग अलग-अलग बातों से अपनी सहमति जताते हैं, जिसमें पैसे खत्म होने की चिंता, हमेशा पीछे रह जाने और ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं कर पाने का अहसास शामिल है।

विचार

बिहार में बड़े भाई की भूमिका में चुनाव लड़ेगी भाजपा- एनडीए गठबंधन का फॉर्मूला तय हो गया

बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दिलचस्प दौर जारी है। नीतीश कुमार जहां एक बार फिर अपने पुराने रूप में आते हुए लालू यादव और राबड़ी देवी पर तीखा हमला बोल रहे हैं। नीतीश तेजस्वी यादव पर निशाना साधने के साथ ही बिहार के मतदाताओं को 2005 से पहले के बिहार की भी लगातर याद दिला रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की लड़ाई के बीच प्रशांत किशोर के एक बयान ने बिहार की राजनीति को पूरी तरह से गरमा दिया है। जन सुराज पार्टी के बैनर तले बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे प्रशांत किशोर ने यह बयान देकर सनसनी पैदा कर दी है कि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ मिलकर विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे लेकिन नतीजों के बाद वे फिर से पाला बदल सकते हैं। प्रशांत किशोर ने इसके साथ ही अपने कई पुराने बयानों को दोहराते हुए नीतीश कुमार के स्वास्थ्य पर भी कई तरह के गंभीर सवाल उठाए। भाजपा के रणनीतिकारों को भी नीतीश कुमार की राजनीतिक शैली का बखूबी अंदाजा है। इसलिए पार्टी के रणनीतिकारों ने पहले ही इसे ध्यान में रखते हुए अपनी रणनीति बना ली है। बताया जा रहा है कि भाजपा इस बार बिहार के विधानसभा चुनाव में बड़े भाई की भूमिका में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। वर्ष 2020 में हुए पिछले विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन में जेडीयू और भाजपा के बीच 122-121 के फॉर्मूले पर सीटों का बंटवारा हुआ था। जेडीयू को मिले 122 सीटों में से 115 पर नीतीश कुमार ने अपने उम्मीदवार खड़े किए थे और 7 सीटें जीतन राम मांझी की पार्टी को दिया था। वहीं भाजपा ने अपने कोटे की 121 सीटों में से 110 पर अपने उम्मीदवार खड़े किए थे और 11 सीटें मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी को दे दी थी। पिछले विधानसभा चुनाव में 110 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली भाजपा को 74 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। जबकि भाजपा से ज्यादा यानी 115 सीटों पर चुनाव लड़ने के बावजूद नीतीश कुमार की पार्टी सिर्फ 43 सीटों पर ही जीत हासिल कर पाई थी।

इस बार भाजपा ने बिहार में जेडीयू से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने की रणनीति तैयार कर ली है। इस रणनीति के तहत भाजपा ने पिछले विधानसभा चुनाव के 122-121 के फॉर्मूले को दरकिनार करते हुए 139-104 का नया फॉर्मूला तैयार कर लिया है। इस फॉर्मूले के हिसाब से 2020 के विधानसभा चुनाव में 115 सीटों पर लड़ने वाले नीतीश कुमार की पार्टी को इस बार सिर्फ 104 सीटों पर ही संतुष्ट होना पड़ेगा।

अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर उच्छृंखलता नामंजूर

सुप्रीम कोर्ट ने अभिव्यक्ति की आजादी से जुड़े दो अलग-अलग मामलों की सुनवाई के दौरान जो कहा, वह जहां संवैधानिक और लोकतांत्रिक मूल्यों के लिहाज से खासा अहम है वही एक संतुलित एवं आदर्श समाज व्यवस्था का आधार भी है। सुप्रीम कोर्ट ने अभिव्यक्ति की आजादी व धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने से जुड़े इन मामलों में जो फैसले किए हैं और इस दौरान जो टिप्पणियां की हैं, उसके निहितार्थों को समझने की आवश्यकता है। मंगलवार को 'मियां-टियां' और 'पाकिस्तानी' शदों के इस्तेमाल से जुड़ी याचिका की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने इस मुकदमे के आरोपी को इस आधार पर आरोप-मुक्त कर दिया कि यह भारतीय दंड सहिता की धारा 298 के तहत धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के अपराध के बराबर नहीं है। वैसे, अदालत ने इन शदों के प्रयोग को गैर-मुनासिब माना।

एक दूसरे रणवीर इलाहाबादिया से जुड़े मामले में अश्लीलता के आरोपों पर भी सुप्रीम कोर्ट ने बेहद संतुलित लेकिन धारदार-सख्त टिप्पणी करते हुए स्पष्ट किया कि न तो अश्लीलता के लिए कोई गुंजाइश छोड़ी जानी चाहिए और न ही इसे अभिव्यक्ति की आजादी की राह में आने देना चाहिए। रणवीर इलाहाबादिया को पॉडकास्ट जारी रखने की इजाजत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि वह नैतिकता और अश्लीलता की सीमा को लांघने की गलती न करें। सुप्रीम कोर्ट ने अभिव्यक्ति की आजादी से जुड़ी इन जटिल होती स्थितियों को गंभीरता से लिया और अनेक धुंधलकों को साफ किया है। सर्वोच्च न्यायालय के इन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के जुड़े फैसलों रूपी उजालों का स्वागत होना ही चाहिए।

यह विडम्बनापूर्ण एवं हमारी न्याय प्रक्रिया की विसंगति ही है कि एक सरकारी कर्मचारी के खिलाफ इस्तेमाल इन 'मियां-टियां' और 'पाकिस्तानी' जैसे शब्दों से जुड़े मुकदमे को निचली अदालत से सर्वोच्च न्यायालय तक का सफर तय करने में लगभग चार साल लगे, मगर दोनों पक्षों ने किसी पड़ाव पर यह समझदारी दिखाने की कोशिश नहीं की कि यह सिर्फ अहं की लड़ाई है। कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी की एक कविता पर गुजरात पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी। गुजरात हाईकोर्ट ने भी इस मामले में जांच की जरूरत बताते हुए पुलिस कार्रवाई की पुष्टि की थी। इसे देखते हुए सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी मायने रखती है कि एफआईआर दर्ज करने से पहले संबंधित अधिकारियों एवं पुलिस को कविता पढ़नी चाहिए थी। कविता नफरत और हिंसा की नहीं, इंसाफ और इश्क की बात करती है। शीर्ष अदालत ने कहा कि आजादी के 75 साल हो गए हैं। कम से कम अब तो पुलिस को स्वतंत्र अभिव्यक्ति का मर्म समझना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की इस बात का संदेश बिल्कुल स्पष्ट एवं न्यायसंगत है। हालांकि यह छिपी बात नहीं है कि पुलिस स्वायत्त तरीके से काम नहीं करती। अनेक कार्रवाइयां उसे सत्ता पक्ष के दबाव में करनी पड़ती हैं। इसलिए विपक्षी दलों एवं समुदाय विशेष के मामले में अगर अभिव्यक्ति की आजादी के कानून को हाशिये पर धकेल दिया या नजरअंदाज कर दिया जाता है, तो हैरानी की बात नहीं। यह कम बड़ी विडंबना नहीं कि साहित्य और कलाओं में अभिव्यक्त विचारों की व्याख्या भी अदालतों को करनी पड़ रही है। सत्ताएं सदा से अपनी आलोचना से तल्ख हो जाती रही है, ऐसी जटिल स्थितियों में आखिर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा कौन करेगा?

ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी कई मौकों पर वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर लम्बी बहसें हो चुकी हैं, आन्दोलन तक हुए, हिंसा एवं अराजकता का माहौल बना। हर बार अदालतें पुलिस को नसीहत देती हैं, अपने दखल से समझ एवं सीख भी देती है ताकि संतुलित वातावरण बना रहे। मगर शायद उस पर संजीदगी एवं संवेदनशीलता से अमल की जरूरत न तो पुलिस ने समझी और न उग्र एवं विध्वंसक शक्तियों ने। इसी का नतीजा है कि अब भी जब तब ऐसे मामले अदालतों में पहुंच जाते हैं, जिनसे किसी की भावना के आहत होने एवं विभिन्न समुदायों के आपसी सौहार्द-सद्भावना के खण्डित होने के आरोप लगते रहते हैं, जबकि वास्तव में उनमें ऐसा कुछ नहीं होता। बेवजह नफरत, द्वेष एवं घृणा का माहौल बनता रहा है, चाहे वह फिल्मों के दृश्यों-संवादों, किसी राजनेता के बयानों, धर्मगुरुओं के बोलों या साहित्य के किसी अंश को लेकर भावनाएं आहत करने या भड़काने के आरोप किसी ऐतिहासिक-मिथकीय प्रसंग को लेकर की गई टिप्पणी पर लगते रहे हों।

आज सोशल मीडिया जैसे मंचों के बेजा इस्तेमाल की प्रवृति बढ़ रही है, फेसबुक, ट्विटर, यू-ट्यूब जैसे सोशल मंचों पर ऐसी सामग्री परोसी जा रही है, जो अशिष्ट, अभद्र, हिंसक, भ्रामक, राष्ट्र-विरोधी एवं समुदाय विशेष के लोगों को आहत करने वाली होती है, जिसका उद्देश्य राष्ट्र को जोड़ना नहीं, तोड़ना है। इन सोशल मंचों पर ऐसे लोग सक्रिय हैं, जो तोड़-फोड़ की नीति में विश्वास करते हैं, वे चरित्र-हनन और गाली-गलौच जैसी औछी हरकतें करने के लिये उद्यत रहते हैं तथा उच्छृंखल एवं विध्वंसात्मक नीति अपनाते हुए अराजक माहौल बनाते हैं। एक प्रगतिशील, सभ्य एवं शालीन समाज में इस तरह की हिंसा, अश्लीलता, नफरत और भ्रामक सूचनाओं की कोई जगह नहीं होनी चाहिए, लेकिन विडम्बना है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कानून के चलते सरकार इन अराजक स्थितियों पर काबू नहीं कर पा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया से जुड़े मंचों के दुरुपयोग पर चिंता से सहमति जताते हुए भी सेंसरशिप और नॉर्म (मानदंड) के बीच के फर्क को रेखांकित किया। उसका कहना था कि सरकार को इस संबंध में गाइडलाइंस लानी चाहिए, लेकिन ऐसा करते हुए यह भी ध्यान में रखना जरूरी है कि वे अभिव्यक्ति की आजादी पर गैरजरूरी पाबंदियों का रूप न ले लें।

सुप्रीम कोर्ट के इस सख्त रुख की अहमियत इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि यह ऐसे समय सामने आया है जब देश में अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर विभिन्न समुदायों का विचलन, द्वेष एवं नफरत काफी बढ़ी हुई दिख रही है। शासन प्रशासन की ओर से इन्हें रोकने की कोशिशों में भी अक्सर अति-उत्साह की झलक देखने को मिलती है। हालांकि सोशल मीडिया के ये मंच स्वस्थ लोकतंत्र के लिए एक सकारात्मक भूमिका भी निभाते देखे जाते रहे हैं। उन पर कड़ाई से बहुत सारे ऐसे लोगों के अधिकार भी बाधित होने का खतरा है, जो स्वस्थ तरीके से अपने विचार रखते और कई विचारणीय मुद्दों की तरफ ध्यान दिलाते हैं। मगर जिस तरह बड़ी संख्या में वहां उपद्रवी, हिंसक, राष्ट्रीय और सामाजिक समरसता को छिन्न-भिन्न करने वाले तत्त्व सक्रिय हो गए हैं, उससे चिंता होना स्वाभाविक है। इससे जहां नागरिकों के अभिव्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन होता है, वहीं इसके गलत इस्तेमाल की बेजा स्थितियां भी देखने को मिलती है। शीर्ष अदालत ने याद दिलाया है कि इस अधिकार का ख्याल रखा जाए। उन पर अंकुश लगाने एवं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई का प्रावधान करना जरूरी है।

भारत की संप्रभुता और अखंडता, देश की सुरक्षा, विदेशी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता या नैतिकता, न्यायालय की अवमानना, मानहानि या किसी अपराध के लिए उकसाने के विरुद्ध वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं दी जा सकती है। सरकार इनकी रक्षा के लिए भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध लगा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने अभिव्यक्ति की आजादी के अधिकार के साथ-साथ सेंसरशिप के प्रति अपनी अनिच्छा को दोहराया। लेकिन यह भी कहा कि ऐसा विचार 'घटिया विचारों' और 'गंदी बातों' का लाइसेंस नहीं है। दरअसल, इन दिनों सोशल मीडिया में जिस पैमाने पर विष-वमन हो रहा है, उसने पुलिस की चुनौतियां बढ़ा दी हैं। मगर उसकी कार्रवाइयां इसलिए प्रभावी नहीं होतीं, क्योंकि राज्य-दर-राज्य उनके पीछे के राजनीतिक पक्षपात भी स्पष्ट हो जाते हैं। राज्य पुलिस अक्सर सरकार विरोधी पोस्ट के मामले में तो तत्परता दिखाती है, मगर सत्तारूढ़ दल से जुड़े लोगों की वैसी ही गतिविधियां वह नजरअंदाज कर देती है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने उचित ही गुजरात पुलिस को एहसास कराया है कि उसे असामाजिक तत्वों से निपटते हुए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बुनियादी लोकतांत्रिक मूल्य की रक्षा भी करनी है। जाहिर है, उच्छृंखल हुए बिना आजादी के उपयोग में ही नागरिक का भी भला है और समाज का भी।

मोटापे से जाता है देश में भुखमरी-कुपोषण को रोकने का रास्ता

भारत विडम्बनाओं से भरा देश है। इन्हीं में से एक है मोटापा और भुखमरी। इनमें एक जुड़ाव भी है। एक तरफ अनावश्यक और अत्यधिक खाने से बढने वाला मोटापे से होने वाली बीमारियां राष्ट्रव्यापी समस्या बनती जा रही है, वहीं दूसरी तरफ आबादी का एक बड़े हिस्सा दो वक्त का भरपेट भोजन नसीब नहीं होने से कुपोषित होकर रोगग्रस्त हो रहा है। यदि मोटापा खत्म या नियंत्रित हो जाए तो इससे भुखमरी व कुपोषण के लिए धन की कमी पूरी हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 119वी श्रृंखला में देश में बढ़ती मोटापे की समस्या पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि पिछले कुछ वर्षों में मोटापे के मामले दोगुने हो गए हैं और भारत में मोटापे की व्यापकता पर ध्यान देने की तत्काल आवश्यकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम सब मिलकर छोटे-छोटे प्रयासों से इस चुनौती से निपट सकते हैं। जैसे एक तरीका है कि खाने के तेल में 10 पर्सेंट की कमी करना। भोजन में खाद्य तेल की खपत को कम करने के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए प्रधानमंत्री ने देश के दस प्रसिद्ध लोगों को नॉमिनेट किया। मोटापा सिर्फ सेहत का मसला नहीं, बल्कि अर्थव्यवस्था के लिए भी खतरा है। एक नई स्टडी के अनुसार, भारत में मोटापे का आर्थिक बोझ 2030 तक बढ़कर 6.7 लाख करोड़ रुपये प्रति वर्ष हो जाएगा। यह लगभग 4,700 रुपये प्रति व्यक्ति होगा, जोकि जीडीपी का 1.57 फीसदी है। ग्लोबल ओबेसिटी ऑब्जर्वेटरी के अनुसार, 2019 में मोटापे का आर्थिक प्रभाव 2.4 लाख करोड़ रुपये था। यह लगभग 1,800 रुपये प्रति व्यक्ति और जीडीपी का 1.02 फीसदी था। 2060 तक यह आंकड़ा बढ़कर 69.6 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है, जो प्रति व्यक्ति 44,200 रुपये और जीडीपी का 2.5 फीसदी होगा। यह स्टडी बताती है कि मोटापा सिर्फ एक स्वास्थ्य समस्या नहीं, बल्कि अर्थव्यवस्था के लिए भी बड़ा खतरा है।

नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे-5 के अनुसार, पुरुषों और महिलाओं में क्रमशः 44 प्रतिशत और 41 प्रतिशत लोग अधिक वजन या मोटापे से ग्रस्त हैं। पिछले सर्वेक्षण में यह आंकड़ा क्रमशः 37.7 फीसदी और 36 फीसदी था। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि मोटापे की समस्या तेजी से बढ़ रही है। विश्व मोटापा महासंघ ने कहा कि भारत में दुनिया में मोटे व्यक्तियों का तीसरा सबसे बड़ा प्रतिशत है। किसी व्यक्ति को तब मोटापे की श्रेणी में रखा जाता है जब उसका बीएमआई 27.5 से अधिक हो। पिछले 10 वर्षों में, भारत की मोटापे की दर लगभग तीन गुनी हो गई है, जिसका असर देश की शहरी और ग्रामीण दोनों आबादी पर पड़ रहा है। मोटापे का वैश्विक संकट सभी उम्र के लोगों को प्रभावित कर रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में मोटापे की दर अधिक है, जो देश के तेज़ आर्थिक विस्तार और बदलती जीवन शैली मानकों के साथ मेल खाता है। भारत में 100 मिलियन से अधिक लोग मोटापे से जूझ रहे हैं। भारत में 12 प्रतिशत पुरुष और 40 प्रतिशत महिलाएं पेट के मोटापे से ग्रस्त हैं। केरल (65.4 प्रतिशत), तमिलनाडु (57.9 प्रतिशत), पंजाब (62.5 प्रतिशत) और दिल्ली (59 प्रतिशत) में यह दर बहुत ज़्यादा है।

मध्य प्रदेश (24.9 प्रतिशत) और झारखंड (23.9 प्रतिशत) में यह दर कम है। आंकड़ों के अनुसार, भारत में पहले से ही 14.4 मिलियन बच्चे मोटे हैं। भारत में बचपन में मोटापे के प्राथमिक कारणों में खराब आहार विकल्प, निष्क्रियता और एक गतिहीन जीवन शैली शामिल है। प्रोसेस्ड

स्नैक्स और फास्ट फूड की बढ़ती लोकप्रियता के कारण बच्चे उच्च कैलोरी, कम पोषक तत्व वाले आहार खा रहे हैं, जिससे वजन बढ़ता है और मोटापा होता है। बचपन में मोटापे के परिणाम व्यापक हैं और लंबे समय में बच्चों के स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। मोटे बच्चों को टाइप 2 मधुमेह, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग और सांस लेने में कठिनाई जैसी दीर्घकालिक स्वास्थ्य समस्याएं होने का उच्च जोखिम होता है। इसके अतिरिक्त, उन्हें निराशा और खराब आत्मसम्मान सहित मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का अनुभव होने की अधिक संभावना है, जो उनके सामान्य स्वास्थ्य को खराब कर सकता है। विडम्बना यह है कि देश मोटापे से होने वाली चुनौतियों से जूझ रहा है, वहीं कुपोषण की समस्या से भी जूझ रहा है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट 2024 में 127 देशों में भारत का स्थान 105वां है। हालांकि पिछले सालों की तुलना में इस साल भारत की रैंक में सुधार हुआ है। लेकिन भारत अभी भी गंभीर भूख की समस्याओं वाले देशों में शामिल है। 2024 की रिपोर्ट में भारत का स्कोर 27.3 है जो भुखमरी के एक गंभीर स्तर को दर्शाता है।

रिपोर्ट में हाल के वर्षों में भारत में कुपोषण के प्रसार में मामूली वृद्धि का उल्लेख किया गया है। भारत की रैंकिंग अपने पड़ोसी देशों श्रीलंका, नेपाल, म्यांमार और बांग्लादेश से पीछे हैं, जबकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान से केवल ऊपर है। श्रीलंका 56, नेपाल 68 और बांग्लादेश 84वें स्थान पर भारत से काफी आगे हैं। भारत में कुपोषण की जो स्थिति है वो किसी से छिपी नहीं है। यहां बहुतों को तो पेट भर खाना भी नहीं मिलता और जिनको मिल भी रहा है उनके भोजन में पोषण की भारी कमी है। इसका खामियाजा नन्हें बच्चों को उठाना पड़ रहा है। भारत को अभी भी बाल कुपोषण जैसी गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें विश्व स्तर पर बच्चों में दुबलापन (18.7 प्रतिशत) सबसे अधिक है। देश में बच्चों के बौनेपन की दर 35.5 प्रतिशत, पांच साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर 2.9 प्रतिशत और कुपोषण का प्रसार 13.7 प्रतिशत है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी एक रिपोर्ट में भारत में पोषण की स्थिति गंभीर बताई गई है। रिपोर्ट के आंकड़ों के मुताबिक देश में पांच वर्ष से कम उम्र के 31.7 फीसदी बच्चे स्टंटिंग का शिकार हैं। मतलब की यह बच्चे अपनी उम्र के लिहाज से ठिगने हैं। यह रिपोर्ट लेवल्स एंड ट्रेंड इन चाइल्ड मालन्यूट्रिशन 2023 संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (यूनिसेफ), विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) और वर्ल्ड बैंक द्वारा संयुक्त रूप से जारी की गई थी। बाल कुपोषण एक गंभीर मुद्दा बना हुआ है, जिसमें दुबलापन और बौनापन दोनों ही खतरनाक रूप से उच्च स्तर पर हैं। इंपीरियल कॉलेज लंदन द्वारा की गई इस रिसर्च के मुताबिक भारतीय किशोर, नीदरलैंड के समान आयु वर्ग के बच्चों की तुलना में 15.2 सेमी ठिगने हैं। इसी तरह यदि वेस्टिंग यानी ऊंचाई के लिहाज से वजन को देखें तो देश में भारत में पांच वर्ष या उससे कम आयु के 18.7 फीसदी बच्चों का वजन उनकी ऊंचाई के हिसाब से कम था। मतलब की 2020 में इस आयु वर्ग के देश के करीब 2.2 करोड़ बच्चे वेस्टिंग का शिकार थे। मोटापे की समस्या से निपटना बहुत मुश्किल काम नहीं है। जीवनशैली और खानपान में बदलाव के साथ नियमित व्यायाम इत्यादि से इस समस्या को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। यह समस्या व्यक्तिगत है, इसलिए देश के हर व्यक्ति की निजी जिम्मेदारी है कि वह अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखे।

ऐसा करने से व्यक्ति और उसके परिवार के साथ देश का भी नुकसान नहीं होगा। असल चुनौती तो कुपोषण और भुखमरी की भयावहता से निपटने की है। यह समस्या मोटापे की तरह व्यक्तिगत नहीं है। इसके लिए मौजूदा और पिछली केंद्र की सरकारों के साथ राज्यों की सरकारें भी जिम्मेदार हैं। इस समस्या से निपटने के लिए धन और भ्रष्टाचार रहित पारदर्शी नीति की आवश्यकता है। विशेषकर मोटापे से होने वाले आर्थिक नुकसान को रोक कर कुपोषण और भुखमरी जैसी अमानवीय समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। राजनीतिक दल जब तक अपने निहित क्षुद्र स्वार्थों को छोड़ कर ऐसे राष्ट्रीय मुद्दों पर एकराय नहीं होंगे तब तक इस तरह की समस्याएं देश की विडम्बनाओं को उजागर करने के साथ ही देश की तरक्की के कथित पैमानों को मुंह चिढ़ाती रहेंगी।

कार में आग लगी, जिंदा जला युवक

बेकाबू होकर पहले पेड़ से टकराई, 4 लोग घायल, बालाघाट से छत्तीसगढ़ लौट रहे थे

मीडिया ऑडीटर, बालाघाट (एजेंसी)। बालाघाट में एक कार पेड़ से टकरा गई। टक्कर होते ही कार में आग लग गई। एक युवक जिंदा जल गया। 4 लोग गंभीर घायल हैं।

हादसा दिनी-पुनी के मुरमाड़ी मार्ग पर शुक्रवार सुबह करीब 4 बजे हुआ। रामपायली थाना पुलिस के मुताबिक, छत्तीसगढ़ के दुर्ग से आए पांच युवक कटंगी में शादी समारोह में शामिल होकर लौट रहे थे। मुरमाड़ी में उनकी कार बेकाबू होकर पेड़ से टकरा गई और उसमें आग लग गई।

कार सवार चार लोग किसी तरह कार से बाहर निकल गए, लेकिन 24 साल का राकेश श्रीवास अंदर ही फंसा रह गया। सुबह घूमने निकले ग्रामीणों ने हादसे की सूचना रामपायली पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बाहर निकाला। थाना प्रभारी चंद्रजीत यादव के अनुसार, मृतक के परिजनों के आने के बाद ही पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जाएगा।

कार सवार सत्यप्रकाश पटले (27) और कृष्णा साहू (18) को गोंदिया रेफर किया गया है। श्लोक जोशी (29) और विक्रम खांडे (19) का इलाज बालाघाट जिला अस्पताल में चल रहा है। घायल अभी बात करने की स्थिति में नहीं हैं।

अरपा भैंसाझार परियोजना घोटाला, राजस्व निरीक्षक बर्खास्त

सरकार को हुआ 3.42 करोड़ का नुकसान, पटवारी रहते रिकॉर्ड में की थी हेराफेरी

मीडिया ऑडीटर, बिलासपुर (एजेंसी)। बिलासपुर जिले के विजयपुर, तखतपुर के राजस्व निरीक्षक मुकेश साहू को शासकीय सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। साहू पर भ्रष्टाचार कर शासन को 3.42 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाने का आरोप है।

यह मामला अरपा भैंसाझार परियोजना के मुआवजा घोटाले से जुड़ा है। साहू ने पटवारी के कार्यकाल में रिकॉर्ड में अवैध बदलाव किए। इससे भू-स्वामियों को अधिक मुआवजा मिला और शासन को राजस्व की हानि हुई।

सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका: कलेक्टर ने मामले की जांच के लिए कमेटी गठित की थी। साहू ने इस कार्रवाई को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। लेकिन, कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि पटवारी कार्यकाल की जांच कराने के लिए कलेक्टर सक्षम प्राधिकारी हैं।

जांच में पाया गया कि साहू ने पटवारी हल्का नंबर 45 सकरी में पदस्थ रहते हुए भू-अर्जन प्रकरण में अनियमितताएं की। जुलाई 2021 की प्रारंभिक जांच में गंभीर अनियमितताएं मिलीं। इसके बाद उन्हें शो कॉज नोटिस दिया गया। जवाब संतोषजनक नहीं होने पर उन्हें निलंबित कर दिया गया।

जनवरी 2025 के जांच प्रतिवेदन में आरोप प्रमाणित होने पर संचालक भू-अभिलेख छत्तीसगढ़ ने साहू को बर्खास्त करने का आदेश दिया। विभागीय जांच में सिद्ध हुआ कि साहू के कार्यों से शासन को 3 करोड़ 42 लाख 17 हजार 920 रुपए की आर्थिक क्षति हुई। 8 साल की कानूनी लड़ाई के बाद यह मामला निष्कर्ष तक पहुंचा है।

जानिए क्या था पूरा मामला: राजस्व निरीक्षक मुकेश साहू ने अपने पटवारी कार्यकाल में अरपा भैंसाझार परियोजना के अंतर्गत चकरभाठा वितरक नहर निर्माण में अधिगृहित भूमि ग्राम सकरी 0.90 एकड़ भूमि को व्यवसायिक परिवर्तित भूमि दर्ज किया।

अभिलेख में अवैधानिक रूप से सुधार करने के कारण भूस्वामी मनोज अग्रवाल को मुआवजा राशि 3 करोड़ 4 लाख 80 हजार 49 रुपए का भुगतान किया गया। पटवारी साहू के द्वारा अभिलेख में अवैधानिक रूप से सुधार करने के कारण शासन को 3.42 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ।

हाईवा ने बाइक को मारी टक्कर

तमनार के युवक की मौत, साथी गंभीर, नेहरू चौक के पास हुआ हादसा

मीडिया ऑडीटर, बिलासपुर (एजेंसी)। बिलासपुर में नेहरू चौक के पास सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। गुरुवार को तेज रफ्तार हाईवा ने बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि तमनार निवासी अविनाश पटेल की मौके पर ही मौत हो गई।

सिविल लाइन थाना क्षेत्र का मामला है। अविनाश अपने दोस्त चैतन्य कर्ष के साथ बाइक पर कही जा रहा था। तभी यह हादसा हुआ। घटना में चैतन्य भी गंभीर रूप से घायल हो गया। आसपास के लोगों ने तुरंत डायल 112 को सूचना दी।

घायल का इलाज जारी: डायल 112 के जवान धीरेंद्र तोमर मौके पर पहुंचे। उन्होंने घायल चैतन्य को तत्काल अस्पताल पहुंचाया। सिविल लाइन पुलिस को भी घटना की जानकारी दी गई। पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घायल चैतन्य का अस्पताल में इलाज जारी है।

टैक्स नहीं देने पर केसरी पाइप फैक्ट्री सील

अतिक्रमण पर चला निगम का बुलडोजर, 3 ट्रॉली सामान जब्त, 25 हजार जुर्माना

मीडिया ऑडीटर, बिलासपुर (एजेंसी)। बिलासपुर में नगर निगम ने टैक्स जमा नहीं करने वालों पर सख्ती दिखाई है। पहली बार बड़ी कार्रवाई करते हुए सालों से संपत्ति समेत अन्य टैक्स नहीं पटाने पर निगम ने केसरी पाइप फैक्ट्री को सील कर दिया है। वहीं, कब्जामुक्त सड़क के लिए गांधी चौक से जगमल चौक तक नगर निगम अतिक्रमण शाखा की टीम ने कार्रवाई करते हुए 3 ट्राली सामान जब्त की। इस कार्रवाई के दौरान सामानों की जब्ती बनाने पर दयालबंद में जमकर विवाद हुआ। दयालबंद में सड़क पर छड़ रखने पर सलूजा स्टील पर 25 हजार जुर्माना भी किया गया।

दरअसल, निगम कमिश्नर अमित कुमार ने ऐसे सभी बड़े बकायादारों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई के निर्देश दिए हैं, जिन्होंने सालों से टैक्स ही जमा नहीं किया है। वित्तीय वर्ष के अंतिम तारीख तक बकाया राजस्व तेजी से वसूलने और लक्ष्य पूरा करने को कहा है।

निगम कमिश्नर के निर्देश के बाद वसूली में लगे राजस्व विभाग ने सिर्फ फरवरी माह में ही 4 करोड़ 74 लाख 32 हजार रुपए की वसूली की है और मार्च महीने में 1 से 5 मार्च तक 2 करोड़ 2 लाख 81 हजार रुपए राजस्व वसूला है। वित्तीय वर्ष की समाप्ति में अभी 25 दिन बाकी हैं। हालांकि टारगेट के हिसाब से वसूली नहीं हो पा रही है।

केसरी पाइप फैक्ट्री को किया सील: टिकरापारा स्थित केसरी पाइप फैक्ट्री का 2016-17 से अब तक 33 लाख 84 हजार 354 रुपए राजस्व बकाया था। कई बार नोटिस देने के बावजूद फैक्ट्री के संचालक ने ध्यान नहीं दिया ना ही बकाया राशि जमा की गई। नोटिस के बावजूद बकाया राशि जमा नहीं करने पर निगम कमिश्नर अमित कुमार ने फैक्ट्री को सील करने के निर्देश दिए। जिस पर गुरुवार को अतिक्रमण और राजस्व अमले ने केसरी पाइप फैक्ट्री को सील कर दिया।

अतिक्रमण हटाने पर जमकर मचाया बवाल: इधर, शहर की सड़कों पर दुकान संचालकों और ठेले वालों का कब्जा रहता है। इसके चलते सड़कें सकरी हो गई हैं। इससे ट्रैफिक भी बाधित होता है। निगम कमिश्नर अमित कुमार के निर्देश पर गुरुवार को नगर निगम अतिक्रमण शाखा और यातायात पुलिस की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की।

कार्रवाई गांधी चौक से शुरू हुई, जो जगमल चौक तक चली। इस दौरान दयालबंद में जमकर विवाद हुआ। दयालबंद में सलूजा स्टील द्वारा सड़क पर कब्जा करते हुए छड़ रख दी गई थी। इसके चलते ट्रैफिक बाधित हो रहा था। इस पर निगम ने सख्ती दिखाते हुए संचालक पर 25 हजार का जुर्माना किया। इसके बाद निगम ने पुराना बस स्टैंड, तेलीपारा, शनिचरी समेत अन्य जगहों में जाकर ट्रैफिक बाधित करने वाले ठेले को जब्त किया। अतिक्रमण शाखा प्रभारी प्रमिल शर्मा और शिव जायसवाल का कहना है कि अभी कार्रवाई अलग-अलग जगहों पर चलेगी।

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर विशेष लेख

महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए हो रही है नई इबारत

हम सभी भलीभाती जानते है कि हर वर्ष 8 मार्च को पूरी दुनिया में अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। यह दिन महिलाओं के अधिकार, समानता और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के साथ ही उनके साथ होने वाले किसी भी प्रकार के भेदभाव को रोकने के उद्देश्य से समर्पित होता है। महिलाओं की भूमिका समाज के हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण रही है, फिर चाहे वह परिवार हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, राजनीति हो या उद्योग-धंधे ही क्यों हो महिलाओं की भागीदारी के बिना कोई भी विकास कार्य अधूरा है, और यह समझते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने महिला सशक्तिकरण को अपनी पहली प्राथमिकता बनाया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं की शुरुआत की है।

छत्तीसगढ सरकार की योजना महिलाओं की सुरक्षा और

आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ा कदम:- *छत्तीसगढ़ सरकार की मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना गरीब परिवारों की बेटियों के विवाह के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करती है, जिससे बाल विवाह जैसी कुरीतियों पर अंकुश लगा है और लड़कियों को शिक्षा के लिए प्रेरित किया गया है। हालांकि एमसीबी जिले में पिछले एक वर्षो से इस योजना के तहत अब तक किसी भी लाभार्थी को सहायता नहीं मिल पाया है, जिसे लेकर एमसीबी जिले में कुछ महीनों बाद कन्या विवाह होने की हो रही है, जिसे लाभार्थियों को लाभ मिल सकता है ।*

राज्य में महिला सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सखी वन स्टॉप सेंटर की स्थापना की गई, जहां पीड़ित महिलाओं को कानूनी, चिकित्सा और मानसिक परामर्श सेवाएं दी जाती हैं। साथ ही महिला स्व-सहायता समूहों को प्रोत्साहन देकर उन्हें रोजगार और व्यापार के अवसर दिए जा रहे हैं, जिससे वे आर्थिक रूप से मजबूत हो रही हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े के नेतृत्व में एमसीबी जिले में मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान को बड़े स्तर पर लागू किया गया है, जिससे 4247 गर्भवती महिलाओं और बच्चों को पोषणयुक्त आहार उपलब्ध कराया जा रहा है।

आंगनबाड़ी केंद्रों से बदल रही हैं महिलाओं और बच्चों की ज़िंदगी:- एमसीबी जिले में महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जिले में कुल 1138 आंगनबाड़ी केंद्र स्वीकृत हैं और उसमें से सभी 1138 केंद्र संचालित किए जा रहे हैं। वर्तमान में सरकार की ओर से 1087 आंगनबाड़ी भवनों की स्वीकृति मिली है, जिनमें से 996 भवन संचालित हो रहे हैं। इन केंद्रों के माध्यम से महिलाओं और बच्चों को पोषण, शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं दी जा रही हैं, जिससे कुपोषण और शिशु मृत्यु दर में कमी आई है।

जिले में महिला की आर्थिक सशक्तिकरण विकास की नई दिशा:- जिले में स्वास्थ्य और पोषण के क्षेत्र में सुकन्या समृद्धि योजना के तहत 7302 लड़कियों को आर्थिक सहायता दी गई है। वहीं नोनी सुरक्षा योजना के तहत अबतक 2303 बेटियों को सुरक्षा कवच प्रदान किया गया है। वहीं महतारी वंदन योजना के तहत 1,00,372 महिलाओं को लाभ मिल रहा है, इस महतारी वंदन योजना के तहत महिलाओं के खाते में अब तक 12 किस्तें जारी कर दिया गया हैं। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए महिला स्व-सहायता समूहों को सरकार द्वारा वित्तीय सहायता और प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है, जिससे वे कृषि, दुग्ध उत्पादन, हस्तशिल्प और छोटे उद्योगों में भाग ले रही हैं। एमसीबी जिले की कई महिलाओं ने इन योजनाओं का लाभ उठाकर आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कदम बढ़ाया है और अब वे अन्य महिलाओं के लिए प्रेरणा बन रही हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाएं महिलाओं के उज्जवल भविष्य की नींव कल्पना है:- *प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की केन्द्र सरकार ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है, जिससे वे गर्भावस्था के दौरान सही पोषण और चिकित्सा सुविधा प्राप्त कर सकें। मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को छोटे व्यवसाय शुरू करने के लिए बिना गारंटी के ऋण दिया जा रहा है, जिससे वे अपने पैरों पर खड़ी हो सकें। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भी कई महिलाओं को अपने घर का मालिकाना हक मिला है, जिससे उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है। एमसीबी जिले में इन योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन किया गया है। यहां की कई महिलाओं ने सरकार की योजनाओं का लाभ उठाकर अपने जीवन को संवारने का कार्य किया है।*

महिलाओं का सशक्तिकरण ही सशक्त समाज की नई पहचान:- अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस केवल एक दिन का उत्सव नहीं, बल्कि एक संकल्प है कि महिलाओं को समान अवसर, अधिकार और सम्मान दिया जाए। छत्तीसगढ़ सरकार, महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल से महिलाओं का जीवन बदल रहा है। एमसीबी जिले में आंगनबाड़ी केंद्रों का विस्तार, पोषण अभियान, सुकन्या समृद्धि योजना, नोनी सुरक्षा योजना और महतारी वंदन योजना जैसे कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है। आने वाले वर्षों में इन योजनाओं को और अधिक प्रभावी बनाकर महिला सशक्तिकरण की इस दिशा को और आगे ले जाने की जरूरत है। जब महिलाएं सशक्त होंगी, तो परिवार, समाज और देश भी सशक्त होगा। यही एक सशक्त छत्तीसगढ़ और आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ता कदम है।

मणिपुर केंद्रीय विश्वविद्यालय का 18 सदस्यीय दल पहुंचा शैक्षणिक भ्रमण पर

मीडिया ऑडीटर, एमसीबी (निप्र)। केंद्रीय विश्वविद्यालय मणिपुर के प्रोफेसर एवं छात्र-छात्राओं का 18 सदस्यों का दल विगत दिवस गोंडवाना मरीन फॉसिल्स पार्क मनेंद्रगढ़ पहुंचा। कलेक्टर डी.राहुल वेंकट के निर्देशानुसार जिले के पुरातत्व एवं पर्यटन विभाग के नोडल अधिकारी डॉ. विनोद पांडेय ने मणिपुर विश्वविद्यालय के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर माइबाम विद्यानंदा एवं एमएससी अर्थ साइंस के छात्र एवं छात्राओं को फॉसिल्स पार्क के बारे में की विस्तार से जानकारी दी। इस दौरान नोडल अधिकारी ने दल को चिरमिरी हल्दीबाड़ी खदान एवं खान बचाव केंद्र मनेंद्रगढ़ का भ्रमण भी कराया।

इस अवसर पर वी.डी. गर्ग सदस्य जिला पुरातत्व संघ उपस्थित रहे। मरिन फॉसिल पार्क भ्रमण करने आये दल को जिला शिक्षा अधिकारी अजय मिश्रा ने भी सभी छात्र-छात्राओं को शुभकामनाएं दी।

28 करोड़ वर्ष प्राचीन गोंडवाना फॉसिल्स पार्क, छत्तीसगढ़ के अलावा देश के अन्य राज्यों के शोधार्थी एवं पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है साथ ही जिला प्रशासन व वन विभाग पार्क के सौंदर्यकरण एवं विकास हेतु लगातार प्रयास कर रहे है।

बिलासपुर निगम को हाईकोर्ट से मिली राहत

कंसल्टेंट कंपनी को अब नहीं देने होंगे 4.07 करोड़, कमर्शियल कोर्ट का आदेश निरस्त

मीडिया ऑडीटर, बिलासपुर (एजेंसी)। बिलासपुर नगर निगम को हाईकोर्ट ने राहत देते हुए कमर्शियल कोर्ट के आदेश को निरस्त कर दिया है। कमर्शियल कोर्ट ने नगर निगम को कंसल्टेंट कंपनी को 4.07 करोड़ रुपए का भुगतान करने का आदेश दिया था। पूरा मामला स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम के भुगतान को लेकर है। दरअसल, नगर निगम ने 15 जुलाई 2010 को स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम के लिए योजना और डिजाइनिंग का काम करने कंसल्टेंट की नियुक्ति करने टेंडर जारी किया। प्रक्रिया पूरी करने के बाद सिंगापुर की मैनहार्ट कंपनी को काम मिला। एग्रीमेंट के अनुसार प्रोजेक्ट की कुल लागत का 1.18 फीसदी राशि कंसल्टेंट को मिलनी थी।

इसके लिए 24 जनवरी 2011 को एग्रीमेंट हुआ। कंपनी को 33.53 करोड़ रुपए का डीपीआर बनाकर देना था। लेकिन, कंपनी ने सर्वे कर 333.93 करोड़ रुपए का डीपीआर बना दिया। मैनहार्ट कंपनी ने इस लागत पर 1.18 फीसदी के आधार पर 4. 7 करोड़ रुपए की मांग की।

कमर्शियल कोर्ट पहुंचा मामला: नगर निगम ने कंपनी को इतनी राशि देने से इनकार कर दिया। इस पर कंपनी ने मध्यस्थता के लिए मामला प्रस्तुत किया। मध्यस्थ ने 7 फरवरी 2018 को कंसल्टेंट के पक्ष में फैसला दिया। साथ ही नगर निगम को 4.07 करोड़ रुपए कंपनी को भुगतान करने का आदेश दिया।

आदेश के अनुसार तीन माह के भीतर रकम नहीं देने पर 9 फीसदी वार्षिक ब्याज के साथ राशि दी जानी थी। निगम ने मध्यस्थ के आदेश को कमर्शियल कोर्ट में चुनौती दी। लेकिन, कमर्शियल कोर्ट से निगम की अपील खारिज हो गई।

हाईकोर्ट ने निगम के पक्ष में दिया फैसला: जिसके बाद नगर निगम ने कमर्शियल कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की। हाईकोर्ट ने नगर निगम के पक्ष में फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि प्रोजेक्ट की अंतिम लागत को सरकार की मंजूरी नहीं मिली थी। इसलिए, कंसल्टेंट की फीस का दावा गलत था। हाईकोर्ट ने मध्यस्थ और कंसल्टेंट के आदेश को निरस्त कर दिया है। हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद नगर निगम को अब यह राशि नहीं देनी होगी।

44.26 लाख की जगह मांगे 4.7 करोड़ रुपए: कंपनी को डीपीआर बनाने के लिए 44.26 लाख मिलना था। लेकिन, कंपनी ने 333.93 करोड़ के प्रोजेक्ट के हिसाब से 4 करोड़ 7 लाख रुपए की मांग की। इस दौरान निगम द्वारा भुगतान नहीं किए जाने पर मामला कोर्ट में चला गया।

बिलासपुर के कोनी में बनेगा नया तहसील कार्यालय

9 करोड़ रुपए की स्वीकृति, 3 मंजिला भवन में मिलेगी सभी सुविधाएं

मीडिया ऑडीटर, बिलासपुर (एजेंसी)। बिलासपुर के नेहरू चौक स्थित तहसील कार्यालय अब कोनी में ट्रांसफर होगा। राज्य शासन ने इस नए भवन के लिए 9 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। कमिश्नर कार्यालय के समीप बनने वाला यह तीन मंजिला भवन आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा।

कलेक्टर अवनीश शरण ने उप मुख्यमंत्री अरुण साव और वित्त मंत्री ओपी चौधरी से इस प्रोजेक्ट की स्वीकृति मांगी थी। नए भवन के बनने से नेहरू चौक की भीड़ और सड़क जाम की समस्या से लोगों को राहत मिलेगी।

वर्तमान तहसील कार्यालय में स्थान की कमी है। एक कमरे में कई शाखाएं चल रही हैं। रिकॉर्ड रूम की स्थिति खराब है। बारिश में कोर्ट रूम में पानी रिसता है।

नया भवन बेसमेंट और भूतल सहित तीन मंजिला होगा। हर तल का क्षेत्रफल लगभग 1250 वर्गमीटर होगा। बेसमेंट और भूतल में पार्किंग, लिफ्ट, कैंटीन और शौचालय की सुविधा होगी।

पहले तल पर छह कोर्ट रूम, कानूनगो कक्ष और अन्य कार्यालय होंगे। दूसरे तल पर एसडीएम कोर्ट रूम, वीसी रूम, रिकॉर्ड रूम, डेटा सेंटर और अन्य सुविधाएं होंगी। सभी तलों पर महिला, पुरुष और दिव्यांगजनों के लिए अलग शौचालय की व्यवस्था की होगी।

जिले का अनोखा घाघरा मंदिर बिना जोड़ वाली पत्थरों की बना है रहस्यमयी संरचना

मीडिया ऑडीटर, एमसीबी (निप्र)। छत्तीसगढ़ के मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले में स्थित घाघरा मंदिर ऐतिहासिक और रहस्यमयी धरोहरों में से एक है। यह मंदिर जिले के मुख्यालय मनेंद्रगढ़ से लगभग 130 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और जनकपुर के पास घाघरा ग्राम में स्थित है। मंदिर की विशेषता यह है कि इसका निर्माण बिना किसी जोड़ने वाली सामग्री के, केवल पत्थरों को संतुलित करके किया गया है। यह अपने अनोखे निर्माण और झुकी हुई संरचना के कारण रहस्य और कौतूहल का केंद्र बना हुआ है।

बिना किसी जोड़ के पत्थरों से निर्मित यह मंदिर अद्भुत स्थापत्य कला का उदाहरण: घाघरा मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इस मंदिर में पत्थरों को जोड़ने के लिए किसी भी प्रकार की गारा-मिट्टी, चूना या किसी अन्य पदार्थ का प्रयोग नहीं किया गया है। केवल पत्थरों को सही संतुलन के साथ रखकर इस भव्य मंदिर का निर्माण किया गया है। यह तकनीक प्राचीन भारतीय स्थापत्य कला और इंजीनियरिंग कौशल को दर्शाती है। इतना ही नहीं इस मंदिर का झुकाव भी इसे और अधिक रहस्यमयी बनाता है। इतिहासकारों और विशेषज्ञों का मानना है कि यह मंदिर किसी भूगर्भीय हलचल या भूकंप के कारण झुक गया होगा। हालांकि, सदियों पुराना यह मंदिर आज भी मजबूती से खड़ा है, जो इसकी निर्माण शैली की उत्कृष्टता को दर्शाता है।

मंदिर के निर्माण काल को लेकर इतिहासकारों में मतभेद हैं। कुछ इतिहासकार इसे 10वीं शताब्दी का मंदिर मानते हैं, जबकि कुछ इसे बौद्ध कालीन मंदिर बताते हैं। स्थानीय लोगों का विश्वास है कि यह एक प्राचीन शिव मंदिर है, जहां आज भी विशेष अवसरों पर पूजा-अर्चना की जाती है। मंदिर के भीतर किसी मूर्ति का न होना भी इसे और रहस्यमयी बनाता है। स्थानीय जनश्रुतियों के अनुसार इस मंदिर का निर्माण उस समय की अद्भुत वास्तुकला और तकनीकी कौशल का प्रमाण है। कई शोधकर्ताओं का मानना है कि यह मंदिर बौद्ध काल की किसी विशेष शैली में बनाया गया होगा, लेकिन धीरे-धीरे यह हिंदू परंपरा में समाहित हो गया।

घाघरा मंदिर केवल धार्मिक स्थल ही नहीं बल्कि यह छत्तीसगढ़ के संस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहरों में से एक है। इस मंदिर को देखने के लिए दूर-दूर से पर्यटक और शोधकर्ता आते हैं। मंदिर की रहस्यमयी संरचना और इसके झुके होने की वजह से यह पुरातत्वविदों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। घाघरा मंदिर भारतीय स्थापत्य कला की उस उन्नत तकनीक का उदाहरण है, जो बिना किसी आधुनिक संसाधनों के भी इतनी मजबूत और संतुलित संरचनाएं बनाने में सक्षम थी। छत्तीसगढ़ के पर्यटन स्थलों में इस मंदिर को उचित पहचान मिलने से यह क्षेत्र ऐतिहासिक और धार्मिक पर्यटन का प्रमुख केंद्र बन सकता है।

श्रद्धालु कैसे पहुंचे घाघरा मंदिर: घाघरा मंदिर जाने के लिए सबसे नजदीकी प्रमुख कस्बा जनकपुर है। यहाँ से घाघरा गाँव तक आसानी से पहुँचा जा सकता है। यदि आप मनेंद्रगढ़ से यात्रा कर रहे हैं, तो मंदिर तक पहुंचने में लगभग 130 किलोमीटर की दूरी तय करनी होगी। सड़क मार्ग से यह स्थान आसानी से पहुँचा जा सकता है, और यात्रा के दौरान आप छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक सौंदर्य का भी आनंद ले सकते हैं।

हरियाणा के पंचकूला में एयरफोर्स का फाइटर जेट जगुआर क्रैश

पंचकूला (एजेंसी)। भारतीय वायुसेना का जगुआर लड़ाकू विमान शुक्रवार को हरियाणा के पंचकूला में क्रैश हो गया। एयरक्राफ्ट ने प्रशिक्षण उड़ान के लिए अंबाला एयरबेस से उड़ान भरी थी। पायलट विमान से सुरक्षित बाहर निकल गया। हादसे में किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं मिली है। हादसा पंचकूला के मोरनी में बालदवाला गांव के पास हुआ। वायुसेना ने बताया कि हादसा दोपहर करीब 3.45 बजे तकनीकी खराबी के कारण हुआ। पायलट समझदारी दिखाते हुए विमान को रिहायशी इलाके से दूर ले गया, फिर खुद सुरक्षित रूप से बाहर निकल गया। जिसके बाद ग्रामीणों ने वहां पहुंचकर पायलट को पानी पिलाकर मदद की। हादसे की जांच के लिए वायुसेना के विशेषज्ञों की टीम मौके पर पहुंच गई है। पंचकूला जिले के रायपुररानी के पुलिस अफसर ने फोन पर एजेंसी को बताया कि वायुसेना का विमान पंचकूला जिले के पहाड़ी इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। स्थानीय पुलिस भी मौके पर है।

स्टालिन का चैलेंज-भाजपा चुनाव में ट्राई लैंग्वेज को मुद्दा बनाए

चेन्नई (एजेंसी)। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन शुक्रवार को भाजपा को चैलेंज किया कि हिम्मत है तो विधानसभा चुनाव में ट्राई लैंग्वेज को मुद्दा बनाकर दिखाएं। उन्होंने कहा कि एनकेजी स्टूडेंट पीएचडी होल्डर को समझा रहे हैं। स्टालिन ने अपनी एक्स पोस्ट में केंद्र सरकार पर हिंदी थोपने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु कभी भी इस जबरदस्ती को स्वीकार नहीं करेगा। यह ब्रिटिश शासन जैसा है। शिक्षा मंत्री ने तमिलनाडु को हिंदी स्वीकारने की धमकी दी, अब उन्हें इसका जवाब मिलेगा। वहीं, इसके जवाब में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि स्टालिन ने तमिल के लिए कोई बड़ा काम नहीं किया। वे तमिल भाषा के इतने ही हितैषी हैं तो राज्य में मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई तमिल में शुरू करवाएं। हम पिछले दो साल से यह अनुरोध कर रहे हैं। शाह ने तमिलनाडु के रानीपेट जिले के केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के 56वें ??स्थापना दिवस परेड में ये बाते कहीं।

सुप्रीम कोर्ट का धारावी प्रोजेक्ट पर रोक से इनकार

नई दिल्ली (एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को धारावी रिडेवलेपमेंट प्रोजेक्ट के लिए चल रहे निर्माण कार्य पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। साथ ही बॉम्बे हाईकोर्ट के अडाणी ग्रुप के पक्ष में दिए फैसले को पलटने से भी मना कर दिया। यूएई की कंपनी सेकलिंक टेक्नोलॉजीज कॉर्प ने इस प्रोजेक्ट को अडाणी प्रापर्टीज प्राइवेट लिमिटेड को देने के महाराष्ट्र सरकार के फैसले को चुनौती दी थी। इसी के बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सेकलिंक ने अडाणी ग्रुप का टेंडर रद्द करने की मांग की है। धारावी रिडेवलेपमेंट प्रोजेक्ट एशिया का सबसे बड़ा शहरी पुनर्वास कार्यक्रम माना जा रहा है। पहले जानिए क्या है मामला मुंबई के धारावी को रिडेवलेप करने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने 2019 में टेंडर जारी किया था।

भोपाल के बड़े तालाब के संरक्षण के लिए उठाएं आवश्यक कदम-मुख्यमंत्री डॉ. यादव

भोपाल (एजेंसी)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि भोपाल का बड़ा तालाब हमारी समृद्ध धरोहर का हिस्सा है, सर्वे कराकर इसके संरक्षण के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं। बड़े तालाब के आस-पास हो रहे अवैध निर्माण और सीहोर से बड़े तालाब में आने वाले जल को अवरूद्ध करने वाली संरचनाओं के विरूद्ध कार्रवाई की जाए। सभी जिम्मेदार अधिकारी भोपाल ताल के आस-पास हो रही निर्माण गतिविधियों के प्रति सतर्क रहें और उनके विरूद्ध तत्काल कार्रवाई करें। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने यह निर्देश मुख्यमंत्री निवास में हुई पर्यावरण विभाग की समीक्षा बैठक में दिए। बैठक में मुख्य सचिव श्री अनुराग जैन, अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय डॉ. राजेश राजौरा, सचिव पर्यावरण श्री नवनीत मोहन कोठारी तथा अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश की नदियों तथा अन्य जल संरचनाओं को प्रदूषण से मुक्त रखने के लिए इनके आस-पास की औद्योगिक इकाईयों के प्रति सतर्क रहने की आवश्यकता है। यह सुनिश्चित हो कि औद्योगिक इकाइयों द्वारा उनके यहां से निकलने वाले डिस्चार्ज का प्लांट में ही ट्रीटमेंट किया जाए, बड़े होटलों पर भी यह व्यवस्था लागू हो। बैठक में सिंहस्थ-2028 के दृष्टिगत क्षिप्रा तथा कान्ह नदी के जल की गुणवत्ता की निरंतर मॉनिटरिंग तथा इस संबंध में जनजागृति के लिए विशेष गतिविधियां चलाने के निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि जल संरचनाओं में जल जीवों, जल वनस्पतियों की स्थिति और जल की गुणवत्ता के अध्ययन के लिए विश्वविद्यालयों को भी साथ जोड़ा जाए। नदियों के आस-पास हो रही खनन गतिविधियों को नियंत्रित करना आवश्यक है। इसके साथ ही खनन के बाद छोड़े दिए गए गड्ढों को भरने के लिए नगरीय निकाय और पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का दायित्व निर्धारित किया जाए। खनन के बाद छूटे स्थानों को तालाब के रूप में विकसित किया जा सकता है, इससे आस-पास के क्षेत्र के जल स्तर में भी सुधार होगा।

दिल्ली में महिला सम्मान योजना की लॉन्चिग आज संभव

नई दिल्ली (एजेंसी)। दिल्ली में बीजेपी सरकार 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर महिला समृद्धि योजना का शुरू कर सकती है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए दिए जाएंगे। अनुमान है कि करीब 20 लाख महिलाओं को इस योजना का फायदा मिलेगा। योजना का फायदा उन महिलाओं को मिलेगा जिनकी सलाना आय 3 लाख रुपए से कम है और जो टैक्स नहीं देतीं। योजना का फायदा 18 से 60 साल तक की महिलाओं को मिलेगा जो सरकारी नौकरी नहीं करतीं और जिनको अन्य सरकारी वित्तीय सहायता नहीं मिल रही है।

रजिस्ट्रेशन के लिए 8 मार्च को लॉन्च होगा स्पेशल पोर्टल- महिला समृद्धि योजना का फायदा उठाने के लिए महिलाओं को ई-रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। इसके लिए सरकार 8 मार्च को एक पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च कर सकती है। इस पोर्टल पर महिलाएं अपने जरूरी दस्तावेज, जैसे वोटर कार्ड, बीपीएल कार्ड, आधार कार्ड और आय प्रमाण पत्र जमा करके आवेदन कर सकेंगी।

लगभग 20 लाख महिलाएं को मिलेगा योजना का फायदा- दिल्ली में 72 लाख महिला मतदाता हैं। अनुमान है कि करीब 20 लाख महिलाओं को इस योजना का फायदा मिलगा। इसमें से करीब 50 प्रतिशत महिलाएं मतदाता हैं। सरकार महिला लाभार्थियों की पहचान के लिए अलग-अलग विभागों से डेटा एकत्र कर रही है।

जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में लॉन्च होगी योजना- महिला समृद्धि योजना की शुरुआत के लिए जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इसमें करीब 5 हजार महिलाओं के शामिल होने की संभावना है।

स्टालिन की मौजूदा और पूर्व मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी

चेन्नई (एजेंसी)। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिने ने परिसीमन मामले में अन्य राज्यों के मौजूदा और पूर्व मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखी है। इसमें उन्होंने 22 मार्च को होने वाली जेएसी की पहली बैठक में अपने प्रतिनिधि भेजने का अनुरोध किया है, ताकि परिसीमन मुद्दे पर साझा रणनीति बनाई जा सके। परिसीमन और ट्राई लैंग्वेज पॉलिसी के विरोध में स्टालिन ने 5 मार्च तमिलनाडु में सर्वदलीय की थी। बैठक में इस मुद्दे पर जॉइंट एक्शन कमेटी बनाने का फैसला हुआ था। जेएसी परिसीमन में राज्यों का प्रतिनिधित्व बचाने और प्रक्रिया ईमानदारी से पूरी हो, इसके लिए काम करेगी। स्टालिन- परिसीमन से कम जनसंख्या वाले राज्यों को नुकसान चिट्ठी में स्टालिन ने चेतावनी दी है कि परिसीमन से तमिलनाडु जैसे कम जनसंख्या वाले राज्यों पर असर पड़ेगा। उन्होंने लिखा कि देश में 1952, 1963 और 1973 में परिसीमन हुआ था। 1976 में परिसीमन को साल 2000 के बाद होने वाली पहली जनगणना तक रोक दिया गया। वहीं, 2002 में परिसीमन पर 2026 तक रोक बढ़ा दी गई थी। 2021 की जनगणना में देरी के वजह से परिसीमन तय समय से पहले हो सकता है। इससे अपनी जनसंख्या नियंत्रित रखने वाले राज्य प्रभावित हो सकते हैं। स्टालिन ने दक्षिण में केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक, पूर्वी राज्यों में पश्चिम बंगाल और ओडिशा और उत्तर में पंजाब से जेएसी में शामिल होने के लिए उनकी औपचारिक सहमति मांगी है।

कांग्रेस नेता शमा ने शमी का समर्थन किया

बरेली (एजेंसी)। भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद शमी के रोजा न रखने के विवाद पर कांग्रेस नेता शमा मोहम्मद ने उनका समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि इस्लाम वैज्ञानिक धर्म है। इसमें सफर और शारीरिक मेहनत के दौरान रोजा न रखने की छूट दी गई है। शमा ने कहा- मोहम्मद शमी सफर कर रहे थे और एक खेल में हिस्सा ले रहे थे, जहां उन्हें शारीरिक मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे में रोजा न रखना कोई गुनाह नहीं है। इस्लाम में इंसान के हालात को ध्यान में रखा जाता है। शमा वही नेता हैं जिन्होंने कुछ दिन पहले रोहित की फिटनेस पर सवाल उठाए थे। इस बीच, ऑल

इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने भी शमी के पक्ष में बयान दिया। उन्होंने कहा- कुरान में साफ लिखा है कि अगर कोई बीमार है और सफर पर है, तो वह रोजा छोड़ सकता है। किसी को भी शमी के फैसले पर सवाल उठाने का हक नहीं है। भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी इस वक्त चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए दुबई में हैं। 4 मार्च को वे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल मैच खेल रहे थे। बॉलिंग के बाद वह थक गए तो बाउंड्री लाइन पर एनर्जी ड्रिंक पीते नजर आए। जिसको लेकर विवाद खड़ा हो गया। बरेली के मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने कहा- इस्लाम में रोजा रखना फर्ज है। अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर रोजा नहीं रखता, तो वह इस्लामिक कानून के अनुसार गुनहगार माना जाता है। क्रिकेट खेलना बुरा नहीं है, लेकिन धार्मिक जिम्मेदारियों को भी निभाना चाहिए।

तुगलक रोड का नाम बदलने की अटकलें

नई दिल्ली (एजेंसी)। दिल्ली में एक बार फिर सड़कों के नाम बदलने को लेकर विवाद खड़ा हो चुका है। भाजपा सांसद दिनेश शर्मा और केंद्रीय मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर के सरकारी आवास के बाहर 'तुगलक लेन' की जगह 'विवेकानंद मार्ग' लिखा गया है। हालांकि, अभी आधिकारिक रूप से नाम नहीं बदला गया है। विपक्षी पार्टियां नाम बदलने को इतिहास से छेड़छाड़ बता रही हैं। वहीं भाजपा का कहना है कि मुगल शासकों के नाम हटाकर सड़कों को भारतीय महापुरुषों के नाम पर किया जाना चाहिए 27 फरवरी को दिल्ली विधानसभा के सत्र में भाजपा विधायक नीलम पहलवान ने विधानसभा में नजफगढ़ का नाम बदलने का प्रस्ताव रखा था। उन्होंने नजफगढ़ का नाम बदलकर नाहरगढ़ करने की मांग की। इस दौरान भाजपा विधायक का कहना था कि 1857 की लड़ाई में राजा नाहर सिंह ने लड़ाई लड़के नजफगढ़ क्षेत्र को दिल्ली के प्रांत में शामिल करवाया था। लेकिन कई कागजी कार्रवाई होने के बावजूद भी आजतक नाम नहीं बदला गया। वहीं दक्षिणी दिल्ली के आरके पुरम से भाजपा विधायक अनिल शर्मा ने भी गांव मोहम्मदपुर का नाम बदलने की मांग की।

एलोपैथी दवा भ्रामक विज्ञापन मामला-राज्यों ने सुप्रीम कोर्ट में बताया एक्शन ले रहे हैं, 25 मार्च को अगली सुनवाई होगी

नई दिल्ली (एजेंसी)। एलोपैथी दवा भ्रामक विज्ञापन मामले में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस अभय ओका और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की बेंच ने कहा- हमें बताया गया है कि राज्य भ्रामक विज्ञापनों के खिलाफ सख्त कदम उठा रहे हैं। अगली सुनवाई 25 मार्च का होगी। इससे पहले 10 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने आयुर्वेदिक, सिद्धा और यूनानी दवाओं के अवैध विज्ञापनों पर एक्शन नहीं लेने वाले राज्यों को फटकार लगाई थी। इसमें दिल्ली, जम्मू-कश्मीर और आंध्र प्रदेश का नाम शामिल था। तब कोर्ट ने तीनों राज्यों के मुख्य सचिवों को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया था। जस्टिस ओका- हमने आपका नोट देखा है और हम पाते हैं कि कुछ भी लागू नहीं किया जा रहा है। अब राज्यों द्वारा नियमों का पालन हो रहा है कि नहीं, उस पर विचार करेंगे।

फरासत- मुख्य सचिव मौजूद हैं और उन्होंने अतिरिक्त हलफनामे दायर किए हैं। वे पूरी तरह से अनुपालन नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसमें पर्याप्त सुधार हुआ है। हलफनामों में एक और बात जो स्पष्ट रूप से सामने आ रही है वह यह है कि नियम 170 अब राज्यों द्वारा अंतत: लागू किया जा रहा है। उनके पास 4 तंत्र हैं और वे इसे लागू कर रहे हैं।

कोर्ट- 10 फरवरी, 2025 के आदेश के अनुसार तीनों राज्यों के मुख्य सचिव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हैं। अभी तक देखा गया कि राज्य इस पर काम कर रहे हैं। अगली सुनवाई 25 मार्च को दोपहर 2 बजे की जाएगी। क्या है पूरा मामला दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने 27 अगस्त 2024 को आयुष मंत्रालय की ओर से जारी एक नोटिफिकेशन पर रोक लगा दी थी।

राहुल गांधी का गुजरात दौरा, कांग्रेस ऑफिस में मीटिंग की

अहमदाबाद (एजेंसी)। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस लीडर राहुल गांधी दो दिन के दौरे पर गुजरात पहुंचे। वे 7 और 8 मार्च को यहां रहेंगे। स्थानीय नेताओं ने एयरपोर्ट पर राहुल का स्वागत किया। वे एयरपोर्ट से सीधे कांग्रेस ऑफिस पहुंचे। यहां उन्होंने गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ नेताओं के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। इसमें संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, गुजरात के प्रभारी व महासचिव मुकुल वाशनिक और प्रदेश अध्यक्ष शक्ति सिंह गोहिल शामिल रहे। राहुल शुक्रवार को नेताओं से लेकर वार्ड अध्यक्षों के साथ 9 घंटे में 5 बैठकें करेंगे। गुजरात में 64 साल बाद कांग्रेस का अधिवेशन वहीं, 8 और 9 मार्च को गुजरात में कांग्रेस का भी महाधिवेशन हो रहा है। आखिरी बार कांग्रेस का अधिवेशन भावनगर में 1961 में हुआ था। इस तरह गुजरात में 64 साल बाद कांग्रेस का अधिवेशन होने जा रहा है। इसलिए अधिवेशन से पहले राहुल गांधी 7 और 8 मार्च को गुजरात कांग्रेस की संगठनात्मक तैयारी की समीक्षा करेंगे।

बीते गुजरात चुनावों में शर्मनाक रहा था कांग्रेस का प्रदर्शन गुजरात विधानसभा के बीते दो चुनावों की बात करते हैं। साल 2017 में राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने भाजपा को प्रदेश में कड़ी टक्कर दी थी। हालांकि, 2022 चुनाव में आम आदमी पार्टी के चुनाव लड़ने की वजह से पार्टी के वोट कट गए। 2022 विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 182 में से 156 सीटों पर जीत हासिल की थी।

जबकि कांग्रेस सिर्फ 17 सीटों पर सिमट गई और पहली बार चुनाव लड़ रही आम आदमी पार्टी से 13 प्रतिशत वोट शेयर भी खो दिया था। वहीं, 2024 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने मिलकर चुनाव लड़ा। बावजूद इसके पार्टी 26 में से सिर्फ एक ही सीट अपने नाम कर पाई। 2019 और 2014 में तो पार्टी का खाता भी नहीं खुला पाया था।

भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव टल सकता है

नई दिल्ली (एजेंसी)। बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए अभी और इंतजार करना पड़ सकता है। राज्यों में प्रदेश अध्यक्षों के चुनाव की धीमी गति और 21-23 मार्च तक बेंगलुरु में होने वाली आरएसएस की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक के चलते यह प्रक्रिया अप्रैल तक टल सकती है। इससे पहले अटकलें लगाई जा रही थीं कि 14 मार्च (होली) के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष का ऐलान हो सकता है।

1. राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव में देरी आधे से ज्यादा राज्यों में प्रदेश अध्यक्षों का चुनाव में देरी। जरूरी है, लेकिन अब तक सिर्फ 12 राज्यों में ही यह प्रक्रिया पूरी हो सकी है। चुनाव संपन्न कराने के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षक भेजने और तारीख तय करने में ही 10-12 दिन लग सकते हैं। इसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया चलेगी, जिसमें करीब 12-15 दिन का समय लगेगा।

2. आरएसएस की बैठक में देरी से 24 मार्च तक अंतिम फैसला संभव बीजेपी अध्यक्ष के चुनाव में

देरी का एक कारण आरएसएस की बैठक भी है। बेंगलुरु में होने वाली इस बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और संगठन महासचिव बीएल संतोष समेत 1500 से ज्यादा प्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। आरएसएस के वरिष्ठ अधिकारी 17 से 24 मार्च तक बेंगलुरु में रहेंगे, जिसके चलते बीजेपी नेतृत्व को नए अध्यक्ष पर अंतिम निर्णय लेने के लिए 24 मार्च तक इंतजार करना पड़ सकता है।

3. हिंदू नववर्ष के पहले महीने यानि अप्रैल में ऐलान पर विचार बीजेपी नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को हिंदू अस्मिता से जोड़ना चाहती है। इसलिए माना जा रहा है कि 30 मार्च से शुरू हो रहे हिंदू नववर्ष के बाद घोषणा हो सकती है। ऐसे में पार्टी अध्यक्ष के चुनाव को जनवरी के बजाय हिंदू नववर्ष के पहले महीने यानि अप्रैल में कराने पर विचार कर रही है।

जमू-कश्मीर की महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा का ऐलान

श्रीनगर (एजेंसी)। 7 साल बाद जम्मू और कश्मीर का बजट पेश हो रहा है। इस मौके पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की गठबंधन सरकार के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कई बड़े ऐलान किए। दिल्ली की तरह अब जम्मू-कश्मीर की महिलाओं को भी सरकारी बसों में मुफ्त सफर की सुविधा, और हर घर को 200 यूनिट फ्री बिजली मिलेगी। इसके अलावा 15,000 नए प्राइमरी स्कूल और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मास्टर प्लान तैयार करने का एलान हुआ। साथ ही बजट में अमरनाथ यात्रा के दौरान सुरक्षा और रहने की व्यवस्था को और मजबूत करने की बात भी कही गई। महिलाओं और युवाओं के लिए बड़े ऐलान हर महिला को फ्री बस सफर 1 अप्रैल 2025 से सरकारी और ई-बसों में यात्रा मुफ्त 'लखपति दीदी' योजना -महिलाओं को 40,000 रुपये की आर्थिक मदद शादी पर आर्थिक सहायता बढ़ी ङ्क 5,000 की जगह अब 75,000 रुपये मिलेंगे

बिजली, स्वास्थ्य और शिक्षा में सुधार 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त - हर घर को राहत स्मार्ट मीटर इंस्टॉल होंगे बिजली चोरी रोकने और सप्लाई सुधारने के लिए स्वास्थ्य सेवाएं अपग्रेड सभी जिला अस्पतालों में सिटी स्कैन की सुविधा, 110 करोड़ का बजट बीजेपी बोली- पाकिस्तान की बात करने वालों से सख्ती से निपटा जाए जम्मू-कश्मीर में अवैध खनन पर उमर अब?दुल?ला ने कहा कि हम लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करेंगे। साथ ही अवैध खनन को रोकने के लिए सख्त कदम उठाएंगे। वहीं बजट के बीच हंगामा हुआ कि विधानसभा में पाकिस्तान पर जायदा बाते होती हैं, जो नहीं होनी चाहिए। इस पर विपक्ष नेता सुनील शर्मा ने स्पीकर को चिट्ठी लिखी। पत्र में कहा गया कि पाकिस्तान की चर्चा करने वाले विधायकों से सख्ती से निपटा जाए।

साथ ही पाकिस्तान की जहां भी बात की गई है उन शब्दों को सदन की कार्यवाही से हटाया जाए। उमर अब्दुल्ला बोले- भाजपा से गठबंधन का सवाल ही नहीं, हमारा नजरिया बिल्कुल अलग जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भाजपा और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच गठबंधन की संभावनाओं से इनकार किया। उन्होंने कहा- भाजपा के साथ गठबंधन का सवाल ही नहीं उठता।

शुभमन बने एमआरएफ के ब्रांड एंबेसडर

चेन्नई (एजेंसी)। भारतीय क्रिकेट टीम के उप-कप्तान शुभमन गिल अपने अच्छे प्रदर्शन के कारण लगातार आगे बढ़ रहे हैं। अब दिग्गज कंपनी एमआरएफ लिमिटेड ने शुभमन को अपना ब्रांड एंबेसडर बनाया है। ऐसे में वह भी एमआरएफ के स्टीकर लगे बल्ले से खेलते नजर आयेंगे। एमआरएफ ने एक बयान जारी कर कहा कि शुभमन गिल अब एमआरएफ ब्रांड से जुड़ने वाले विराट कोहली सहित अन्य प्रमुख क्रिकेटरों में शामिल हो गये हैं। उन्हें हाल ही में आईसीसी एकदिवसीय रैंकिंग में नंबर एक बल्लेबाज के रूप में भी मान्यता मिली है। एमआरएफ ने कहा कि वह लंबे समय से क्रिकेट के विकास से जुड़ा रहा है और ऐसा आगे भी होता रहेगा। शुभमन की यह भागीदारी विराट के साथ कंपनी के पहले से जारी सहयोग के अतिरिक्त होगी। एमआरएफ लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के. एम. मैमन ने कहा, ''हम शुभमन गिल को एमआरएफ परिवार में शामिल करते हुए गर्व महसूस कर रहे हैं। उनका खेल प्रभावशाली है और वह जिस तरह क्रिकेट के सभी प्रारूपों में नेतृत्व कौशल दिखाते हैं, वह प्रेरणादायक है। उनकी इस लोकप्रियता का लाभ एमआरएफ को भी मिलेगा।

बुमराह के नहीं होने से मुझपर है अधिक जिम्मेदारी-शमी

दुबई (एजेंसी)। भारतीय क्रिकेट टीम के अनुभवी तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन कर टीम को फाइनल तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई है। शमी ने माना है कि तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के नहीं होने से इस टूर्नामेंट में उनपर अधिक जिम्मेदारी है। इसी कारण उनका ध्यान अपनी लय कायम रखने ओर फिटनेस बनाये रखना रहा है। चोट से उबरकर वापसी कर रहे शमी ने बुमराह की गैर मौजूदगी में नये तेज गेंदबाजी हर्षित राणा और ऑलरांउडडर हार्दिक पांड्या के साथ नई गेंद संभाली। शमी ने अभी तक टूर्नामेंट में 8 विकेट लिए हैं। उन्होंने फाइनल में पहुंचने पर कहा, 'मैं अपनी लय फिर हासिल करके टीम के लिए ज्यादा योगदान देने की कोशिश कर रहा हूं। दो विशेषज्ञ तेज गेंदबाज टीम में नहीं है और मेरे ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी है। शमी ने कहा कि बुमराह की गैर मौजूदगी में उनका कार्यभार बढ़ गया है ऐसे में अपना सौ फीसदी से से ज्यादा योगदान देने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा, 'जब आप अकेले मुख्य तेज गेंदबाज हैं और दूसरा ऑलराउंडर है तो तो कार्यभार रहता है। आपको विकेट के लिए मोर्चे से अगुआई करनी होती है। मुझे इसकी आदत हो गई है और मैं अपना सौ फीसदी से अधिक देने की कोशिश कर रहा हूं। गौरतलब है कि शमी को विश्व कप 2023 के दौरान टखने में चोट लगी थी और वह लंबे ब्रेक पर रहे। उन्होंने कहा कि अब वह लंबे स्पैल फेंकने की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं।

न्यूजीलैंड दौरे पर आकिब ही रहेंगे मुख्य कोच - पीसीबी

लाहौर (एजेंसी)। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसबी) ने पूर्व तेज गेंदबाज आकिब जावेद को न्यूजीलैंड दौरे के लिए अंतरिम मुख्य कोच बनाया है। वहीं पूर्व कप्तान मोहम्मद युसूफ को बल्लेबाजी कोच बनाया गया है। पाक टीम अपने न्यूजीलैंड दौरे में सीमित ओवरों की एक सीरीज खेलेगी। इसी को लेकर पीसीबी के एक अधिकारी ने कहा कि चैम्पियंस ट्रॉफी और न्यूजीलैंड दौरे के बीच समय कम होने के कारण आकिब को ही मुख्य कोच की जिम्मेदारी दी गयी है। वहीं , 'पीसीबी ने इस बीच नये मुख्य कोच को तलाशने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। पिछले साल पीसीबी ने जैसन गिलेस्पी को टेस्ट और गैरी कर्स्टन को सीमित ओवरों के प्रारूप में कोच बनाया था पर दोनों के साथ ही बोर्ड अधिकारियों के मतभेद हो गये थे। ऐसे में इन दोनो ने ही पद छोड़ दिया था। उसके बाद से ही पाक टीम के पास कोई पूर्ण कालिक कोच नहीं है। इसी कारण आकिब को सफेद गेंद की टीम का अंतरिम मुख्य कोच बनाया गया और दक्षिण अफ्रीका तथा वेस्टइंडीज के खिलाफ घरेलू सीरीजो में वह टेस्ट टीम के भी मुख्य कोच भी रहे। वह तीन देशों की सीरीज और चैम्पियंस ट्रॉफी में भी टीम के कोच थे पर सभी में पाक को हार का सामना करना पड़ा।

शेड्यूल पर भड़के डेविड मिलर, दुबई जाने को लेकर पूटा गुस्सा

नई दिल्ली (एजेंसी)। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का फाइनल 9 मार्च को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। न्यूजीलैंड ने गुरुवार को दक्षिण अफ्रीका को हराकर चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में जगह बना ली है, जहां उसका सामना रोहित शर्मा के नेतृत्व वाली भारतीय टीम से होगा। लाहौर में खेले गए दूसरे सेमीफाइनल के दौरान तीन शतक लगे। न्यूजीलैंड के रचिन रविंद्र और केन विलियमसन ने शतक जड़े, जबकि डेविड मिलर ने चैंपियंस ट्रॉफी के इतिहास का सबसे तेज शतक लगाया।

हालांकि, सेमीफाइनल गंवाने के बाद मिलर ने आईसीसी को चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल को लेकर लताड़ लगाई है। डेविड मिलर इस बात से नाराज हैं कि सेमीफाइनल मुकाबले से पहले अफ्रीका की टीम को दुबई जाना पड़ा और फिर वापस लाहौर आना पड़ा। डेविड मिलर की शतकीय पारी अफ्रीका के काम नहीं आई, क्योंकि टीम 363 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 9 विकेट खोकर 312 रन बना सकी। चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल अन्य टीमों के लिए काफी अजीबोगरीब था। साउथ

अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया को ग्रुप स्टेज मैच खत्म होने के बाद पहले सेमीफाइनल मुकाबले के लिए पाकिस्तान से दुभई के लिए उड़ान भरनी पड़ी। क्योंकि भारत और न्यूजीलैंड के बीच लीग चरण का आखिरी मुकाबला खेला जाना बाकी था, इस मैच के रिजल्ट से पता चलता कि ग्रुप में टॉप पर रहते कौन सी टीम क्वालीफाई करेगी। वहीं भारत के साथ संभावित मुकाबले के कारण दोनों टीमों को दुबई के लिए उड़ान भरनी पड़ी। वहीं भारत ने न्यूजीलैंड को आखिरी ग्रुप मैच में शिकस्त दी, जिससे भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला सेमीफाइनल खेला गया और इस कारण से दक्षिण अफ्रीका की टीम को दूसरे सेमीफाइनल के लिए पाकिस्तान वापस लौटना पड़ा। डेविड मिलर ने कहा कि, ये एक घंटे और 40 मिनट की फ्लाइट थी लेकिन हमें ये करना पड़ा। जो कि आइडियल परिस्थिति नहीं थी। सुबह का समय था, मैच के बाद हमें यात्रा करनी थी। फिर हम दुबई शाम 4 बजे पहुंचे और हमने सुबह 7 बजकर तीस मिनट पर हमें वापस आना पड़ा। ये इसे अच्छा नहीं बनाता है। ऐसा नहीं है कि हमने पांच घंटे उड़ान भरी और हमारे पास ठीक होने और स्वस्थ होने के लिए पर्याप्त समय था, लेकिन फिर भी एक आदर्श स्थिति नहीं थी। वहीं मिलर ने भविष्यवाणी की और कहा कि, मैं आपके साथ ईमानदारी से कहूंगा कि मुझे लगता है कि मैं न्यूजीलैंड का समर्थन करूंगा।

आईपीएल 2025 से पहले एसआरएच को झटका, ये धाकड़ गेंदबाज हुआ पूरे टूर्नामेंट से बाहर

नई दिल्ली (एजेंसी)। सनराइजर्स हैदराबाद ने अपने स्क्वॉड में बदलाव कर दिया है। इंग्लैंड के ब्राइडन कार्स चोट के कारण टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। उनकी जगह हैदराबाद ने वियान मुल्डर को अपनी टीम में शामिल किया है। मुल्डर दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी हैं और तेज गेदंबाजी ऑलराउंडर हैं। वियान मुल्डर को अगला सीजन खेलने के लिए 75 लाख रुपये की सैलरी दी जाएगी। आईपीएल 2025 शुरू होने से करीब दो सप्ताह पहले ही सनराइजर्स हैदराबाद ने अपने स्क्वॉड में बदलाव कर दिया है। इंग्लैंड के ब्राइडन कार्स चोट के कारण टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं।

उनकी जगह हैदराबाद ने वियान मुल्डर को अपनी टीम में शामिल किया है। मुल्डर दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी हैं और तेज गेदंबाजी ऑलराउंडर हैं। वियान मुल्डर को अगला सीजन खेलने के लिए 75 लाख रुपये की सैलरी दी जाएगी। बता दें कि, ब्राइडन कार्स को चैंपियंस ट्रॉफी 2025 टूर्नामेंट के दौरान चोट आई थी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनके पैर का अंगूठा चोटिल हो गया था, जिसके बाद उन्हें टूर्नामेंट से बाहर होना पड़ा था। इससे पहले उन्हें भारत के खिलाफ व्हाइट बॉल सीरीज के समय भी मुश्किल का सामना करते देखा गया था। वहीं, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच में भी वो अपनी सर्वश्रेष्ठ फॉर्म में नहीं दिखे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच में उन्होंने 7 ओवरों में ही 69 रन लुटा दिए थे। वहीं आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन में सनराइजर्स हैदराबाद ने ब्राइडन कार्स को 1 करोड़ रुपये की बोली लगाकर खरीदा था। ब्राइडन कार्स का टी20 रिकॉर्ड काफी बढ़िया रहा है। एक गेंदबाजी ऑलराउंडर की भूमिका निभाते हुए उन्होंने अब तक अपने टी20 करियर में 53 विकेट लेने के साथ-साथ 783 रन भी बनाए हैं, जिनमें 2 फिफ्टी शामिल हैं। ऐसे में सनराइजर्स हैदराबाद के लिए बहुत बड़ा झटका कहा जा सकता है।

खिताबी मुकाबले को लेकर परेशान हैं विलियमसन

नई दिल्ली (एजेंसी)। रविवार, 9 मार्च को भारत और न्यूजीलैंड के बीच दुबई में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। वहीं मुकाबले को लेकर कीवी स्टार बल्लेबाज केन विलियमसन का मानना है कि भारत के पास चैंपियंस ट्रॉफी के अपने सभी मैच दुबई में खेलने के कारण वहां की परिस्थितियों को लेकर वास्तविक स्पष्टता है लेकिन साथ ही कहा कि उनकी टीम रविवार को होने वाले फाइनल के लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने कहा कि ये फाइनल मुकाबला और इसमें कुछ भी हो सकता है। विलियमसन ने सीधे तौर पर ये नहीं कहा कि भारत को एक ही स्थान पर खेलने का फायदा मिल रहा है। इसके बजाय उन्होंने इसकी तुलना और न्यूजीलैंड की लाहौर की परिस्थितियों की अच्छी समझ से की। न्यूजीलैंड ने बुधवार को यहां दूसरे सेमीफाइनल में दक्षिण अफ्रीका को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। विलियमसन से जब पूछा गया कि क्या भारत को एक ही स्थान पर खेलने का फायदा मिलेगा। उन्होंने कहा कि, मुझे लगता है कि जब आप कई मैच एक ही स्थान पर खेलते हैं तो चीजों को कैसे आगे बढ़ाना है इसको लेकर आपके पास वास्तविक स्पष्टता होती है। उन्होंने कहा कि, जिस तरह से हमें यहां मौका मिला। हमने भी इस स्थान पर कई मैच खेले और मुझे लगता है कि ये क्रिकेट का हिस्सा है। न्यूजीलैंड ने चैंपियंस ट्रॉफी से पहले पाकिस्तान और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ त्रिकोणीय सीरीज के दो मैच लाहौर में खेले थे। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सेमीफाइनल में शतक लगाने के बाद विलियमसन आत्मविश्वास से भरे हुए हैं और उनकी निगाहें अब फाइनल पर टिक गई हैं। उन्होंने कहा कि, इस पर गौर करने के बजाय हमारा ध्यान अगले मैच पर है। मैच का स्थान और विरोधी टीम निश्चित तौर पर मायने रखते हैं। हमने भी वहां भारत के खिलाफ एक मैच खेला है।

मोहम्मद शमी के रोजा ना रखकर एनर्जी ड्रिंक पीने को लेकर भड़के मोलाना रजवी बरेलवी

नई दिल्ली (एजेंसी)। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने क्रिकेटर मोहम्मद शमी की आलोचना की है। मौलाना ने कहा कि इस्लाम में रोजा को फर्ज करार दिया है। अगर कोई जान-बूझकर रोजा नहीं रखता है तो वह गुनहगार होता है। ऐसा ही क्रिकेटर मोहम्मद शमी ने किया, उन्होंने रोजा नहीं रखा। दरअसल, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए मुकाबले के दौरान शमी एनर्जी ड्रिंक पीते हुए दिखए थे। जिसके बाद उन्हें सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल किया गया। वहीं मोलाना ने तो ये तक कह डाला कि रोजा न रखकर शमी ने बहुत बड़ा गुनाह किया है। शरीयत की नजर में वह मुजरिम हैं। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने कहा कि, इस्लाम के अनिवार्य फर्जों में से एक है रोजा। अगर कोई स्वस्थ पुरुष या महिला रोजा नहीं रखता है तो वह बड़ा अपराधी है। मोहम्मद शमी ने मैच के दौरान पानी या कोई अन्य पेय पदार्थ पी लिया। लोग उन्हें देख रहे थे। अगर वह खेल रहे हैं तो इसका मतलब है कि वह स्वस्थ हैं। ऐसी हालात में उन्होंने रोजा नहीं रखा और पानी भी पी लिया। इससे लोगों में गलत संदेश जाता है। रोजा न रखकर शमी ने गुनाह किया है। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। शरीयत की नजर में वह अपराधी हैं। उन्हें खुदा को जवाब देना होगा। वहीं एक मीडिया चैनल से बात करते हुए मोहम्मद शमी के भाई मोहम्मद जैद ने कहा कि, मुझे ऐसे बयानों पर हंसी आती है। ऐसे लोग महज टीआरपी के लिए बयान देते हैं। जहां तक मुझे लगता है कि इमाम साहब ने भी कुछ किताबें पढ़ीं होंगी। अगर कोई किसी के अंडर है, अगर हमारी टीम कहीं बाहर जा रही है तो उसे रोजे में छूट दी गई है। मेरा मानना है कि इमाम साहब को इन बातों से कोई मतलब नहीं है।

नीदरलैंड के दिग्गज ताइकेमा भारतीय महिला ड्रैग फ्लिकर के साथ काम करेंगे

नई दिल्ली (एजेंसी)। भारत ने 2028 लॉस एंजिल्स ओलंपिक तक अल्पकालिक आधार पर राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम के ड्रैग फ्लिकर के साथ काम करने के लिए नीदरलैंड के दिग्गज ताइके ताइकेमा से करार किया है। ताइकेमा ने पिछले महीने भुवनेश्वर में भारत के एफआईएच प्रो लीग अभियान से पहले 10 से 16 फरवरी तक सात दिवसीय शिविर में भारतीय खिलाड़ियों को प्रशिक्षण दिया था। भारत ने प्रो लीग के घरेलू चरण में इंग्लैंड, जर्मनी, नीदरलैंड और स्पेन के खिलाफ मुकाबला किया था। इस सात दिवसीय शिविर में दीपिका, मनीषा चौहान, सोनम और अन्नू जैसी खिलाड़ियों के साथ-साथ कुछ जूनियर खिलाड़ियों ने भी भाग लिया। ताइकेमा के मार्गदर्शन में शिविर का मुख्य उद्देश्य तकनीकी कौशल को निखारने के साथ ड्रैग फ्लिक की सटीकता में सुधार करना था। भारतीय महिला टीम के मुख्य कोच हरेंद्र सिंह ने कहा कि शिविर खिलाड़ियों के लिए बहुत फायदेमंद रहा और ताइकेमा लॉस एंजिल्स खेलों

तक अल्पकालिक आधार पर टीम के साथ काम करना जारी रखेंगे। उन्होंने कहा, ''ताइकेमा ड्रैग फ्लिक के मामले में सबसे महान दिग्गजों में से एक हैं। मैंने हॉकी इंडिया से उन्हें इस क्षेत्र में सुधार करने में हमारी मदद करने के लिए लाने का अनुरोध किया। वह तकनीक को निखारने और ड्रैग फ्लिक की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए टीम के साथ काम कर रहे हैं।'' हरेंद्र ने कहा, ''ड्रैग फ्लिक करना एक विशिष्ट कौशल है और ताइकेमा भविष्य के शिविर में भी हमारे साथ काम करना जारी रखेंगे।'' हरेंद्र ने इससे दीपिका के प्रदर्शन में सुधार का जिक्र करते हुए कहा, '' हमने दीपिका के साथ निश्चित प्रगति देखी है, खासकर हाल के प्रो लीग मैचों के दौरान। ''इस 45 साल के पूर्व खिलाड़ी को अपने खेल के दिनों में पेनल्टी-कार्नर की सटीकता के लिए जाना जाता था। ताइकेमा ने 11 वर्षों के अपने अंतरराष्ट्रीय करियर में नीदरलैंड की पुरुष टीम के लिए 94 मैचों में 170 गोल किए। उन्हें दुनिया के सबसे खतरनाक पेनल्टी कॉर्नर विशेषज्ञों में से एक माना जाता है। वह 2002 और 2006 चैंपियंस ट्रॉफी, 2006 विश्व कप, 2008 ओलंपिक खेलों और 2010 एफआईएच विश्व कप सहित कई प्रमुख अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंटों में शीर्ष स्कोरर थे। उन्होंने 2022 से 2024 तक चीन की महिला टीम के सहायक कोच के रूप में भी काम किया।

दीपिका ने भी कहा कि उन्हें शिविर से बहुत लाभ हुआ। प्रो लीग में पेनल्टी कॉर्नर से अपने तीन में से दो गोल करने वाली दीपिका ने कहा, ''यह सिर्फ एक सप्ताह का शिविर था, लेकिन यह एफआईएच प्रो लीग के घरेलू चरण के लिए काफी फायदेमंद साबित हुआ। मैंने इस दौरान फुटवर्क, शॉट रिलीज और फिनिशिंग को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित किया। इससे मुझे उन तकनीकी समायोजनों की स्पष्ट समझ मिली जिसे मुझे करने की जरूरत थी।

बीएफआई 'मौलिक' कर्तव्यों को पूरा करने में विफल, मुक्केबाजी के लिए तदर्थ समिति की जरूरत-उषा

नई दिल्ली (एजेंसी)। भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) की प्रमुख पीटी उषा ने मुक्केबाजी के लिए तदर्थ समिति नियुक्त करने के अपने फैसले का बचाव करते हुए कहा कि राष्ट्रीय महासंघ पिछले एक साल में अपनी 'मौलिक जिम्मेदारियों' को पूरा करने में विफल रहा है और 'व्यवस्था को बहाल करने तथा उचित प्रशासन सुनिश्चित करने' के लिए उनका यह कदम जरूरी था। उषा का यह बयान आईओए के उपाध्यक्ष गगन नारंग के 28 फरवरी के पत्र के जवाब में आया है। पूर्व ओलंपिक कांस्य विजेता निशानेबाज ने उन पर 'मनमाने' आदेश जारी करने और खिलाड़ियों के कल्याण को कम करने का आरोप लगाया था।नारंग आईओए कार्यकारी परिषद के सदस्य भी हैं। आईओए के आदेश पर दिल्ली उच्च न्यायालय के स्थगन के बावजूद उषा अपनी रुख पर का दृढ़ता से कायम है। भारतीय मुक्केबाजी महासंघ

(बीएफआई) द्वारा दायर याचिका पर अदालत ने आईओए से जवाब मांगते हुए नोटिस जारी किया है। उषा ने नारंग को भेजे जवाब में कहा, ''...आपके (नारंग) इस दावे में कोई सच्चाई नहीं है कि इस निर्णय या मेरी ओर से किसी कथित मनमानी कार्रवाई के कारण खिलाड़ियों को नुकसान हो रहा है। तदर्थ समिति नियुक्त करने का निर्णय मनमाना नहीं था, बल्कि व्यवस्था बहाल करने, उचित प्रशासन सुनिश्चित करने और खिलाड़ियों के विकास को प्राथमिकता देने के लिए एक आवश्यक कदम था।'' उन्होंने कहा, ''दुर्भाग्यपूर्ण वास्तविकता यह है कि बीएफआई पिछले वर्ष राष्ट्रीय चैंपियनशिप आयोजित करने सहित अपनी मूलभूत जिम्मेदारियों को पूरा करने में विफल रहा है।'' उन्होंने कहा, '' एशियाई खेल (2026) नजदीक आ रहे हैं, ऐसे में नयी प्रतिभाओं की पहचान करने, होनहार मुक्केबाजों का चयन करने और भारत की पदक संभावनाओं को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण या अभ्यास कार्यक्रमों को लागू करने के लिए बहुत कम या कोई प्रयास नहीं किया गया है।''

उषा लंबे समय से कई मुद्दों पर कार्यकारी परिषद के सदस्यों के साथ विवाद में रही हैं। उन्होंने कार्यकारी परिषद के सदस्यों पर भारतीय खेलों की समग्र भलाई के बजाय 'व्यक्तिगत प्राथमिकताओं' को तरजीह देने का आरोप लगाया है। नारंग ने उन्हें पत्र लिखकर बीएफआई के संचालन के लिए तदर्थ समिति बनाने के उनके 'मनमाने' फैसले को वापस लेने की मांग की थी।

इस पूर्व निशानेबाज ने कहा था, ''ऐसे मनमाने आदेश के कारण हमारे खिलाड़ियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है और हमें घरेलू तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बदनाम किया जा रहा है'' आईओए ने 24 फरवरी को देश में मुक्केबाजी के मामलों की देखरेख के लिए पांच सदस्यीय तदर्थ समिति का गठन किया था।

प्रशासनिक अधिकारियों के पास चक्कर लगाने को मजबूर है आदिवासी छात्र

करोड़ों खर्च होने के बाद भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हो रहे आदिवासी छात्रावास के बच्चे

मीडिया ऑडीटर, रीवा (निप्र)। सरकार द्वारा अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए तमाम योजनाएं और व्यवस्थाएं बनाई जाती हैं लेकिन कई बार ऐसी तस्वीर आती हैं कि प्रशासन की पोल खोल देती है। और यह स्पष्ट करती हैं की सरकार द्वारा जो व्यवस्थाएं और योजनाएं बनाई जाती हैं तथा जिनके क्रियान्वयन के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं उनका प्रशासन के द्वारा ठीक ढंग से क्रियान्वयन नहीं किया जाता।

रीवा में अनुसूचित जाति के बच्चों के लिए बनाए गए छात्रावास का कुछ ऐसा ही हाल हैं जहां पर रीवा संभाग के सभी जिले रीवा सतना सीधी सहित अन्य जिलों के छात्र रहकर पढ़ाई करते हैं लेकिन इन छात्रों की शिकायतें प्रशासन से हमेशा बनी रहती हैं जिसमें व्यवस्थाओं के दुरुस्त न होने की शिकायत सबसे ज्यादा होती है जिसको लेकर आए दिन यह प्रशासन की चौखट पर पहुंचते हैं। दरअसल रीवा जिले में शासकीय अनुसूचित जाति महाविद्यालय बालक छात्रावास बनाए गए है जहां सभी छात्रावास में 50 -50 छात्र रहकर अध्ययन करते हैं और बड़ी संख्या में ऐसे छात्रावास संचालित हो रहे हैं जिनके क्रियान्वयन के लिए करोड़ों रुपए आते हैं लेकिन जब जमीनी स्तर पर उतरकर उनकी तस्वीर देखते हैं तो चौंकाने वाली होती है। और यह तस्वीर जमीनी हकीकत को दर्शाती है। यही कारण है कि छात्रों को अपनी मूलभूत जरूरत को पूरा करने के लिए प्रशासन की चौखट खटखटाना पड़ता है। छात्र अपनी व्यवस्थाओं को लेकर आए दिन बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट पहुंचते हैं मगर फिर भी उनकी समस्याओं पर किसी का कोई ध्यान ही नहीं जाता।

दैनिक मीडिया ऑडीटर ने ऐसे ही छात्रों से बात की तो उनकी पीड़ा निकाल कर सामने आई। छात्रों का कहना है कि छात्रावास में प्रमुख समस्या है जहां पर छात्रों को ना बेहतर ढंग से पानी मिल पाता गंदगी का आलम अलग ही देखने को मिलता है साथ ही खाने पीने की व्यवस्था बेहतर नहीं होती। छात्रों का तो यह भी कहना है कि छात्रावास के मेस में समय से भोजन भी उपलब्ध नहीं कराया जाता इसकी शिकायत करने पर अधीक्षक कॉलेज का टाइम बदलवाने की बात करने लगते हैं।

दैनिक मीडिया ऑडीटर की टीम जमीनी हकीकत को जानने के लिए मौके पर पहुंची तो जमीनी हकीकत देखकर होश उड़ गए मोटर पंप तो कर दिया लेकिन वो भी खराब पड़ा है। जिसमे पानी ही नहीं आता बड़ी-बड़ी टंकी बैठा दी गई लेकिन उन पर पानी की एक बूंद नहीं है शौच के लिए बाहर जाना पड़ता है गंदगी का आलम अलग ही देखने को मिलता है और वहां की तस्वीर यह बता रही थी कि करोड़ों रुपए लगा दिए गए लेकिन जमीन जस की तस ही बनी हुई है।

जीडीसी की छात्राओं ने एडी कार्यालय का किया घेराव

मीडिया ऑडीटर, रीवा (निप्र)। कन्या महाविद्यालय की छात्राओं ने आज कॉलेज में व्याप्त अनियमितताओं के संबंध में अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा कार्यालय का घेराव किया। छात्राओं ने अतिरिक्त संचालक को ना सिर्फ कॉलेज में व्याप्त अनियमितताओं के संबंध में ज्ञापन सौंपा बल्कि कॉलेज के प्राचार्य पर तानाशाहीपूर्ण रवैया अपनाने का भी आरोप लगाया है। छात्राओं का कहना है कि कन्या महाविद्यालय सिर्फ नाम का ही महाविद्यालय है। यहां कन्याओं के लिए किसी भी तरह की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। बताया गया हैं कि जब भी छात्राएं अपनी समस्याओं को लेकर प्राचार्य को अवगत कराती हैं तो प्राचार्य उनकी समस्याओं को दूर करना तो दूर सुनना तक उचित नहीं समझतीं। जिसका नतीजा है कि आज छात्राओं को एडी कार्यालय का घेराव करना पड़ा। अतिरिक्त संचालक ने छात्राओं की समस्याओं को सुनते हुए उन्हें दूर करने का आश्वासन दिया है साथ ही कॉलेज की प्राचार्य के खिलाफ की गई शिकायत पर जांच कराए जाने की भी बात कही है।

माहे रमज़ान के पहले जुम्मे पर नमाज़ियों की उमड़ी भीड़

मीडिया ऑडीटर, रीवा (निप्र)। माहे रमज़ान के छठवें रोज़े पर आज रीवा में जुम्मे की नमाज़ सभी इबादतगाहों में पढ़ी गई। नमाज़ के लिए सभी इबादतगाहों में लोगों की भीड़ देखी गई। बच्चों से लेकर बड़े-बूढ़े भी मस्जिद में इबादत करते नज़र आए। इस दौरान अल्लाह को राज़ी करने के लिए दुआओं में हज़ारों हाथ उठे। रमज़ान के पहले जुम्मे पर रीवा की छोटी दरगाह, बड़ी दरगाह, घोघर, बिछिया सहित विभिन्न मस्जिदों में जुम्मे की नमाज़ पढ़ी गई। बतादें कि रमज़ान के महीने में बड़े बूढ़े और बच्चे भी ये फ़र्ज़ रोज़े रखते हैं। ऐसा माना जाता है कि रमज़ान रहमत और बरकत का महीना है। जिसमें अल्लाह अपने बंदों की हर जायज़ दुआओं को क़ुबूल करता है। शहर क़ाज़ी मुफ्ती मोहम्मद मुबारक अज़हरी ने बताया कि रमज़ान के महीने में अल्लाह अपने बंदों को बेशुमार नेमतों से नवाज़ता है। उन्होंने कहा कि ये महीना गुनाहों से तौबा करने का और अल्लाह को राज़ी करने का है।

शहर होगा हरियाली से सराबोर, डिवाइडरों पर लगेंगे 7000 पौधे

मीडिया ऑडीटर, रीवा (निप्र)। शहर की सुंदरता और हरियाली बढ़ाने के उद्देश्य से नगर निगम द्वारा महत्वपूर्ण पहल की जा रही है। निगम आयुक्त डॉ. सौरभ सोनवणे के निर्देशन में शहर के प्रमुख सड़कों और डिवाइडरों पर हरे-भरे एवं आकर्षक पौधे लगाने का कार्य शुरू हो गया है। इस अभियान के तहत विशेष रूप से चयनित 32 प्रकार के तेलंगाना से 7,000 पौधे मंगाए गए हैं, जो शहर की साज-सज्जा को निखारने में अहम भूमिका निभाएंगे। निगम आयुक्त डॉ. सौरभ सोनवणे ने बताया कि नगर निगम लगातार हरियाली को बढ़ावा देने के लिए प्रभावी कदम उठा रहा है। पुलिस लाइन चौक, जयस्तंभ, सिरमौर चौक, कॉलेज चौक रोटरी को हरे-भरे पौधों और फूलों से सुसज्जित किया जा रहा है। साथ ही, सभी मुख्य मार्गों के मॉडल रोड डिवाइडरों पर पौधे लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पौधों की वृद्धि में किसी भी प्रकार की रुकावट न आए, इसके लिए डिवाइडरों में नई मिट्टी डलवाई जा रही है और नियमित रूप से सिंचाई की जा रही है, जिससे पौधे स्वस्थ और हरे-भरे बने रहें। इसके अलावा, झलबदरी तालाब के सौंदर्यीकरण और हरित विकास के तहत 40,000 पौधे मंगाए जाने की योजना है, जिससे शहर और अधिक हरा-भरा और सुंदर दिखेगा एवं पर्यावरण संरक्षण के दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगा। निगम आयुक्त ने शहरवासियों से अपील की है कि वे इस अभियान में सहयोग करें और लगाए गए पौधों की देखभाल में अपनी भूमिका निभाएं। ''रीवा हरित शहर, स्वच्छ शहर'' के संकल्प को साकार करने के लिए नागरिकों की सहभागिता आवश्यक है। आइए, हम सब मिलकर अपने शहर को हरा-भरा और स्वच्छ बनाने में योगदान दें।

पीटीएस चौराहा, नीम चौराहा और स्टेडियम तिराहे से हटा अतिक्रमण, संकट में फूल मंडी

मीडिया ऑडीटर, रीवा (निप्र)। अवैध अतिक्रमण के खिलाफ नगर निगम की कार्रवाई लगातार जारी है। शहर को स्वच्छ सुंदर और अतिक्रमण मुक्त बनाने में जुटे नगर निगम प्रशासन ने अभियान को एक बार फिर गति दी है। नगर निगम कमिश्नर के निर्देश पर अतिक्रमण विरोधी अमले ने शहर के अलग-अलग इलाकों में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। टीम ने शहर के पीटी एस चौराहे पर सड़क के किनारे कब्जा कर बनाई गई दुकानों को हटाया। साथ ही अतिक्रमण कर रखी गई गोमतियों को भी ज़ब्त कर लिया। हालांकि कार्रवाई के दौरान निगम अमले को हल्के-फुल्के विरोध का भी सामना करना पड़ा है। इसी तरह नगर निगम टीम द्वारा बोदा बाग़ स्थित नीम चौराहे, स्टेडियम तिराहे पर भी कार्रवाई की गई है। बताया गया कि उक्त सभी जगहों पर कार्रवाई से पहले अतिक्रमण हटाने की सूचना दी जा चुकी थी और कुछ दिनों की मोहलत भी दी गई थी बावजूद इसके जब अतिक्रमण नहीं हटा तो आज अतिक्रमण अमले को मौके पर पहुंचकर कार्रवाई करनी पड़ी।

फूल मंडी हटाने के लिए हुई मुनादी

रीवा. शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए चलाए जा रहे अभियान की ज़द में अब शहर की फूल मंडी भी आ चुकी है। कोठी कम्पाउंड में मनकामेश्वर मंदिर के पास सड़क के किनारे लगी फूलों की दुकानों से बाधित होने वाले यातायात को सुचारू करने के लिए नगर निगम द्वारा फूलों की दुकानों को हटाने की कवायद शुरू कर दी गई है। बतादें कि आज नगर निगम की ओर से कोठी कंपाउंड परिसर में स्थित फूलों की दुकानों को हटाने के लिए मुनादी कराई गई। जिसे लेकर फूल व्यापारी परेशान हो गए हैं। व्यापारियों का कहना है कि पहले प्रशासन उन्हें दुकान लगाने के लिए स्थाई जगह दे, इसके बाद उनकी दुकानों को हटाया जाए। बतादें कि नगर निगम द्वारा शहर में लगातार अतिक्रमण के खिलाफ कार्यवाही कर अवैध अतिक्रमण को ज़मींदोज़ किया जा रहा है। हाल ही में कोठी कंपाउंड में ही स्थित साई मंदिर के समीप से अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्यवाही की गई थी। इस दौरान फूल मंडी के व्यापारियों को एक सप्ताह का समय दिया गया था। ऐसे में समय अवधि पूरी होने के बाद एक बार फिर नगर निगम ने मुनादी कराते हुए दुकानों को खाली करने का निर्देश दिया है। इसके बाद फूल व्यापारी अब अपनी समस्याओं को लेकर सड़क पर उतर आए हैं।

स्कूल के छत की प्लास्टर गिरने से शिक्षिका घायल

मीडिया ऑडीटर, रीवा (निप्र)। ज़िले के मनगवां थाना क्षेत्र अंतर्गत रघुराजगढ़ के आदिवासी बस्ती कटरा में शासकीय प्राथमिक विद्यालय की छत का प्लास्टर अचानक भरभरा कर गिर गया। इस दौरान बच्चों को पढ़ा रही अतिथि शिक्षिका आकांक्षा दुबे उसकी चपेट में आ गई और गंभीर रूप से घायल हो गई। शिक्षिका को गंभीर अवस्था में उपचार के लिए रीवा के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शिक्षिका के सिर पर गंभीर चोटें आई हैं। अचेत अवस्था में उन्हें एसजीएमएच रीवा लाया गया।

प्रेम विवाह के दो साल बाद महिला ने की खुदकुशी

मीडिया ऑडीटर, रीवा (निप्र)। सामान थाना क्षेत्र में एक नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। महिला की मौत से पहले पति ने मायके वालों को सूचना दे दी थी जिससे मामला और भी संदिग्ध हो गया। मायके वालों का कहना है कि उसने आत्मघाती क़दम उठाने से पहले रोका क्यों नहीं। परिजनों के मुताबिक रामनई निवासी बड़े कोल ने सपना कोल से दो साल पूर्व प्रेम विवाह किया था। शादी के बाद दोनों रतहरा बाईपास में स्थित सीमेंट गोदाम में साथ रहते थे और वहीं दोनों काम करते थे। जहां महिला ने बीती रात आत्मघाती क़दम उठाते हुए अपनी जान दे दी। घटना के बाद पुलिस पति को थाने ले गई, जिससे पूछताछ की जा रही है।

एमआईसी की बैठक में शहर के विकास के लिये हुये कई निर्णय

मीडिया ऑडीटर, रीवा (निप्र)। नगर पालिक निगम रीवा के मेयर-इन-काउंसिल की बैठक महापौर अजय मिश्रा (बाबा) की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में निगम आयुक्त डॉ. सौरभ संजय सोनवणे एवं मेयर-इन-काउंसिल के सदस्य नजमा बेगम, नीतू अशोक पटेल, धनेन्द्र सिंह बघेल, रमा दुबे, रवि तिवारी, मनीष नामदेव, गुलाम अहमद, सूफ्मिा सहफूज़ खान, सु आरती बक्सरिया उपस्थित रहें। वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्यय पत्रक (बजट) पर विचार कर परिषद के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया। लक्ष्मण बाग गौशाला को अनुदान राशि प्रदाय करने की स्वीकृति देते हुए इसके ऑडिट कराने के निर्देश प्रदान किये गये। साथ ही अन्य कार्यों को परिषद में भेजे जाने का निर्णय लिया गया। नगर निगम रीवा क्षेत्रान्तर्गत पुर्नघनत्वीकरण योजनान्तर्गत यातायात नगर मे अन्तर्राज्यीय बस टर्मिनल निर्माण योजना का क्रियान्वयन किये जाने हेतु परिषद में भेजे जाने का निर्णय लिया गया। साथ ही राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की प्रतिमा वार्ड 06 में कलेक्टर कार्यालय के सामने स्थित धरना स्थल में, भारतरत्न, अटल बिहारी बाजपेयी की प्रतिमा वार्ड 07 सिविल लाइन में नव निर्मित अटल पार्क में, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी यमुना प्रसाद शास्त्री जी की प्रतिमा वार्ड मांक 05 सेमरिया तिराहा में लगाये जाने की सैद्धांतिक स्वीकृति हेतु प्रस्ताव परिषद का भेजे जाने का निर्णय लिया गया। पद्मधर पार्क एवं विवेकानन्द पार्क के आरक्षण हेतु किराया पुनर्निर्धारण का प्रस्ताव परिषद के समक्ष रखे जाने का निर्णय लिया गया।

जल जीवन मिशन में हुए 136 करोड़ के भ्रष्टाचार मामले पर लीपापोती में जुटा प्रशासन, अधर में लटकी पड़ी जांच

मीडिया ऑडीटर, रीवा (निप्र)। जल जीवन मिशन के तहत प्रदेश के हर घर नल के माध्यम से पेयजल मुहैया कराने की योजना पर अफसर पलीता लगा रहे हैं। इस योजना में लगातार करोड़ों के घोटाले भ्रष्टाचार का खुलासा होने के बाद भी पीएचई, जल निगम के अफसरों पर आज तक कार्रवाई नहीं हुई है। उधर, रीवा जिले में जल जीवन मिशन में फर्जी कामों के जरिए 136 करोड़ का घोटाला सामने आया है। इधर, सरकार का दावा है कि जांच रिपोर्ट मिलने के बाद व्यवस्था में सुधार किया गया है। बावजूद इसके भ्रष्टाचार में लिप्त कर्मचारी और अधिकारियों पर अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

दरअसल प्रदेश में घर-घर पीने का शुद्ध पानी पहुंचाने के उद्देश्य से 2019 में शुरू की गई जल जीवन मिशन योजना अधर में लटकी है। 2024 में मिशन का कार्य अधूरा होने के बाद केंद्र सरकार ने जुलाई 2024 में मप्र के 1271 सर्टिफाइड गांवों में सर्वे कराया। एक निजी एजेंसी द्वारा किए गए इस सर्वे में केवल 209 गांव ही मानकों पर खरे उतरे। वहीं, 217 गांवों में नल कनेक्शन तो लगाए गए, लेकिन पानी की सप्लाई शुरू नहीं हुई। 13 गांवों में नल कनेक्शन तक नहीं लगाए गए, बावजूद इसके कार्य पूरा दिखा दिया गया। 778 गांवों में जल गुणवत्ता की जांच में 390 सैंपल अमानक पाए गए। रिपोर्ट के अनुसार सबसे बड़ा भ्रष्टाचार रीवा, अलीराजपुर और सिंगरौली जिले के गांवो में है।

ऐसे किया गया मिशन में भ्रष्टाचार

योजना मद	राशि का भुगतान (रुपये में)
हैंडपंप मेंटेनेंस	3,17,72,325
जल जीवन मिशन	130,47,08,870
टीपीआई	74,64,762
आईएसए	85,70,124
वाहन, टाइपिंग	1,02,94,344
कुल घोटाला	136,28,00,000

आईएएस की जांच रिपोर्ट में हुआ था खुलासा

बताया जा रहा है कि जल जीवन मिशन में मिली घोटाले की शिकायतों के बाद रीवा कलेक्टर के निर्देश पर सहायक कलेक्टर एवं आईएएस अधिकारी सोनाली देव की अध्यक्षता में एक जांच कमेटी बनाई गई थी। इस कमेटी में कोषालय अधिकारी आरडी चौधरी, पुष्पराज सिंह, सरदार राहुल भाई पटेल तथा सहायक ग्रेड-3 कृष्णकांत वर्मा ने अभिलेखों की जांच की। कमेटी ने संधारित एवं उपलब्ध कराए गए बाउचर, कैश बुक, स्टाक पंजी, वितरण विवरण, निविदा आदि का परीक्षण किया। साथ ही हैंडपंप मेंटेनेंस, विभिन्न फार्मों को किए गए साल बार भुगतान की रिपोर्ट ली। कमेटी ने जांच में पाया कि ठेकेदार द्वारा काम पूरा किए बिना ही करोड़ों का भुगतान कर दिया गया, बल्कि शासकीय धन की अनियमितता की गई।

यह इंजीनियर पाए गए थे भ्रष्टाचार में जिम्मेदार

रीवा में पदस्थ कार्यपालन यंत्री शरद कुमार सिंह, प्रभारी सहायक यंत्री, एसके श्रीवास्तव, आरके सिंह, एसके सिंह, केबी सिंह, अतुल तिवारी, उपयंत्री संजीव मरकाम, संभागीय लेखाधिकारी विकास कुमार आदि ने विभिन्न मदों में अतियिमितताएं करते हुए भुगतान किया। यह पूर्ण रूप से इस भ्रष्टाचार के लिए जिम्मेदार पाए गए हैं। सरकार ने अभी तक इनके विरुद्ध केवल शोकॉज नोटिस देकर इतिश्री कर ली है।

मामले पर सिविल सेवा अधिनियम 1966 के तहत विभागीय जांच की गई है और जांच के बाद कर्मचारियों पर दंड लगाया जाना था परंतु इन कर्मचारियों पर ऐसी कोई कार्यवाही अब तक नहीं की गई है जो कि निंदनीय है जिसके खातिर मेरे द्वारा कई बार शिकायत भी की गई है परंतु प्रशासनिक अमला किसी भी तरह की कार्यवाही करने की बजाय अब भी लीपापोती में जुटा हुआ है।

***बी के माला**, समाजिक कार्यकर्ता*

राशन कार्डधारियों की ई केवाईसी अपडेट कराने चलेगा अभियान

मीडिया ऑडीटर, रीवा (निप्र)। शासन के निर्देशों के अनुसार खाद्य सुरक्षा योजना से विभिन्न 49 श्रेणियों में लाभान्वित हितग्राहियों का सत्यापन किया जा रहा है। खाद्य सुरक्षा योजना से लाभान्वित सभी परिवारों की ई केवाईसी अपडेट करके पोर्टल पर दर्ज की जा रही है। इसके लिए जिले की सभी उचित मूल्य दुकानों में 10 मार्च से 31 मार्च तक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के संबंध में कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल ने बताया कि अभियान के दौरान खाद्य सुरक्षा योजना से लाभान्वित प्रत्येक परिवार की ई केवाईसी दर्ज की जाएगी। कलेक्टर ने कहा है कि सभी एसडीएम तथा खाद्य विभाग के अधिकारी मिलकर प्रत्येक उचित मूल्य दुकान में अभियान का प्रभावी क्रियान्वयन करें। उचित मूल्य दुकान शेष बचे परिवारों की ई केवाईसी दर्ज करने के लिए 31 मार्च से पहले घर-घर जाकर जानकारी प्राप्त करें। इसे ऑनलाइन तय समय सीमा में दर्ज कराएं।

कलेक्टर ने कहा कि प्रत्येक उचित मूल्य दुकानदार प्रतिदिन औसतन 20 हितग्राहियों की ई केवाईसी दर्ज करे। राशनकार्ड में परिवार के सदस्यों के आधार कार्ड अथवा अन्य विवरण यदि सही दर्ज नहीं हैं तो उसे सुधारने की सुविधा पीओएस मशीन में उपलब्ध है। एम राशन पोर्टल पर सेल्समैन ई केवाईसी अपडेट करके दर्ज करें। इसे सहायक आपूर्ति अधिकारी प्रतिदिन सत्यापित करें। सेल्समैन वृद्ध, दिव्यांग और बच्चों की ई केवाईसी घर जाकर ही करें। पीओएस मशीन के माध्यम से ई केवाईसी के शेष हितग्राहियों की जानकारी ली जा सकती है। सभी सहायक आपूर्ति अधिकारी उचित मूल्य दुकानदार शेष बचे हितग्राहियों की सूची निकालकर सेल्समैन को उपलब्ध कराएं। सेल्समैन राशनकार्ड में दर्ज हितग्राहियों में से मृत, पलायन कर गए अथवा डुप्लीकेट सदस्य को ग्राम पंचायत सचिव अथवा शहरी क्षेत्र में वार्ड प्रभारी के माध्यम से पोर्टल से हटाने की कार्यवाही करें। पिछले लगातार चार माह से उचित मूल्य दुकान से राशन न लेने वाले हितग्राहियों के नाम भी पोर्टल से हटाने की कार्यवाही करें। जिन हितग्राहियों की जानकारी में किसी भी तरह की त्रुटि है उसका सुधार करके एम राशन पोर्टल पर दर्ज कराएं।

कलेक्टर ने कहा है कि अभियान की अवधि में प्रत्येक उचित मूल्य दुकान, ग्राम पंचायत और शहरी क्षेत्र में प्रत्येक वार्ड में शिविर लगाएं। शिविर की तिथि की एक दिन पहले से हितग्राहियों को सूचना दें। सार्वजनिक स्थल पर बैठकर राशन कार्डधारियों के ई केवाईसी को पोर्टल में दर्ज करने की कार्यवाही करें। सभी एसडीएम ई केवाईसी दर्ज करने के लिए सेल्समैन, ग्राम पंचायत सचिव, ग्राम रोजगार सहायक, वार्ड प्रभारी तथा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की ड्यूटी लगाएं।

मऊगंज जिले में प्रत्येक पंचायत में आज होगा नारी चौपाल का आयोजन

मीडिया ऑडीटर, रीवा (निप्र)। अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मऊगंज जिले में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों में महिलाओं के सशक्तीकरण, स्वरोजगार, आर्थिक विकास, शैक्षिक विकास तथा जागरूकता से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस संबंध में जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग ने बताया कि मऊगंज जिले में अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को सभी ग्राम पंचायतों में नारी चौपाल का आयोजन किया जा रहा है। इसके माध्यम से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत कमजोर महिलाओं को आजीविका मिशन से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। वंचित बालिकाओं तथा महिलाओं को इन कार्यक्रमों में विशेष तौर पर शामिल किया जाएगा। विभाग के तहत गठित शौर्यादलों द्वारा हाईरिस्क गर्भवती महिलाओं से भेंट कर उन्हें स्वास्थ्य रक्षा और सुपोषण की समझाइश दी जाएगी।

स्वत्वाधिकारी मुद्रक/प्रकाशक संदीप द्विवेदी द्वारा मीडिया ऑडीटर पब्लिकेशन प्रा.लिमि. राजीव मार्ग निराला नगर रीवा से मुद्रित कर मीडिया ऑडीटर कार्यालय राजीव मार्ग निराला नगर रीवा से प्रकाशित, **संपादक संदीप द्विवेदी**, आर.एन.आई नं. 69082/97, डाक पंजीयन क्र.- म. प्र./ रीवा संभाग/ 46/2023-2025, प्रधान कार्यालय रीवा (सिटी कार्यालय चक्रधर सिटी सेंटर रीवा) फोन. नं. 9589645803, 7974467831 Mediaauditor1@gmail.com सभी विवादों का न्याय क्षेत्र रीवा होगा।